website: www.royalpatrika.com
G-mail: royalpatrika@gmail.com
Yahoo: royal_patrika@yahoo.com

R.N.I. No. RAJHIN/2012/48736

दैनिक रॉयल पत्रिका

वर्ष :13 | अंक : 261 | पेज: 8 | जयपुर, शुक्रवार 29 अगस्त 2025 | मूल्य: 1.50 रुपये

हॉकी एशिया कप 2025 आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा- पीएम मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। इसी खास दिन से बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की शुरुआत होगी। टूर्नामेंट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों और टीमों को शुभकामनाएं दीं और विश्वास जताया कि यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "29 अगस्त (जो राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद की जयंती भी है) से राजगीर में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की शुरुआत होगी। मैं एशिया की सभी प्रतिभागी टीमों, खिलाड़ियों, अधिकारियों और समर्थकों को शुभकामनाएं देता हूं।"

उन्होंने कहा कि भारत और एशिया के करोड़ों लोगों के दिलों में हॉकी का हमेशा एक खास स्थान रहा है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि यह टूर्नामेंट रोमांचक मुकाबलों, असाधारण प्रतिभाओं के प्रदर्शन और अविस्मरणीय पलों से भरपूर होगा, जो भविष्य की पीढ़ियों को खेल के प्रति प्रेरित करेगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि हाल के वर्षों में बिहार बड़े खेल आयोजनों का केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने लिखा, "यह गर्व की बात है कि बिहार हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी कर रहा है। हाल में यहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, एशिया रग्बी अंडर-20 सेवन्स चैंपियनशिप 2025, सेपकटकरॉ वर्ल्ड कप 2024 और विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जैसे बड़े टूर्नामेंट आयोजित हुए हैं। यह सब बिहार के विकसित होते खेल बुनियादी ढांचे, जमीनी स्तर पर बढ़ते उत्साह और नई प्रतिभाओं को आगे लाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है।"

टूर्नामेंट में टीमों को दो समूहों में बांटा गया है। भारत को ग्रुप-ए में रखा गया है, जिसमें जापान, चीन और कजाकिस्तान शामिल हैं। वहीं ग्रुप-बी में बांग्लादेश, साउथ कोरिया, मलेशिया और चीनी ताइपे खेलेंगे। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 29 अगस्त को चीन के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 31 अगस्त को जापान से भिड़ेगी और 1 सितंबर को कजाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी।

भागवत बोले- संघ सरकार के फैसले नहीं लेता: हम सिर्फ सलाह देते हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने साफ कहा कि संघ का काम सरकार चलाना नहीं है। उन्होंने कहा कि "संघ केवल सलाह देता है, निर्णय लेना सरकार का काम है।" भागवत ने स्पष्ट किया कि भाजपा और संघ के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं होते।

भागवत ने कहा कि संघ एक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन है, जो समाज में जागरूकता और संगठन शक्ति बढ़ाने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार को फैसले जनता के हित में लेने होते हैं, और संघ केवल अपनी सोच साझा कर सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और संघ दोनों का मूल लक्ष्य राष्ट्रहित है। "नीतियों और तरीकों को लेकर असहमति हो सकती है, लेकिन लक्ष्य और भावना में कोई फर्क नहीं है," उन्होंने जोड़ा।

विश्लेषकों का मानना है कि भागवत का यह बयान ऐसे समय आया है, जब केंद्र की कुछ नीतियों को लेकर संघ और भाजपा के बीच अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं।

चुनाव आयोग की सीपीआई के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और बेहतर बनाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के साथ संवाद का सिलसिला जारी रखा है। इसी कड़ी में आज गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के महासचिव डी. राजा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में आयोग के सामने प्रतिनिधिमंडल ने कई सुझाव भी रखे।

चुनाव आयोग ने बताया कि बीते 150 दिनों में विभिन्न स्तरों पर कुल 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गईं। इनमें मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) द्वारा 40, जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) द्वारा 800 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा 3,879 बैठकें शामिल थीं। इन बैठकों में अब तक 28,000 से अधिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हो चुके हैं।

इसके अलावा, आयोग ने राष्ट्रीय और राज्यीय दलों के नेताओं के साथ 21 से अधिक बैठकें की हैं, जिनमें भाजपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे प्रमुख दलों ने हिस्सा लिया। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देना और राजनीतिक दलों की चिंताओं व सुझावों को सीधे आयोग तक पहुंचाना है। ईसीआई ने कहा कि यह पहल आयोग के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसके तहत मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुरूप सभी हितधारकों के साथ मिलकर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जा रहा है।

गौरतलब है कि इससे पहले 21 अगस्त को जनता दल (सेक्युलर) के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से मुलाकात कर अपने सुझाव दिए थे। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों ने हाल ही में बीजू जनता दल (बीजद) के प्रतिनिधिमंडल से भी चर्चा की थी।

SI भर्ती रद्द होने पर सियासी सरगर्मी: बेनीवाल ने नाचकर जताई खुशी

-युवाओं ने कहा- "तानाशाही हारी, बेरोजगारों की जीत"

जयपुर। राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। लंबे समय से भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने फैसले के बाद समर्थकों के साथ डांस कर खुशी जताई। वहीं, जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे युवाओं ने भी इसे ऐतिहासिक जीत बताया।

बेनीवाल बोले- मंत्री और अफसर भर्ती बचाने में लगे थे

हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी के मंत्री और कई अधिकारी नहीं चाहते थे कि भर्ती रद्द हो। लेकिन युवाओं की लड़ाई रंग लाई। उन्होंने कहा- "अब कई नेता क्रेडिट लेने के लिए दौड़ेंगे। सबको पता है कौन युवाओं के साथ खड़ा रहा और कौन पीठ दिखाकर भाग गया। अगर कोर्ट का फैसला विपरीत आता तो हम दिल्ली कूच करते।"

बेनीवाल ने यह भी दोहराया कि उनकी लड़ाई भर्ती माफिया के खिलाफ है।

युवाओं की जीत का जश्न

जयपुर में शहीद स्मारक पर लंबे समय से धरने पर बैठे युवाओं ने कोर्ट के फैसले पर जश्न मनाया। युवाओं ने कहा- "आज बहुत खुशी का दिन है। चार साल की मेहनत रंग लाई। आज तानाशाही हारी है और बेरोजगारों की जीत हुई है।"

किरोड़ी बोले- 50% से ज्यादा अभ्यर्थी फर्जी

राज्य के मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने भी कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में उन्होंने भर्ती में धांधली को लेकर आंदोलन किया था। "सरकार ने सिर्फ 58 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े, लेकिन मेरे पास मौजूद दस्तावेज़ बताते हैं कि 50% से ज्यादा फर्जी उम्मीदवार भर्ती में सिलेक्ट हुए थे। अगर ऐसे लोग सर्विस में आते तो प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ जाती।"

देरी से मिला न्याय

किरोड़ी मीणा ने माना कि फैसले में देरी जरूर हुई, लेकिन इसे प्रदेश के हित में सही कदम बताया। अब भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से कराई जाएगी।

जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकी ढेर

नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर घुसपैठ की कोशिश को सेना ने गुरुवार को नाकाम कर दिया, जिसमें दो आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि गुरेज सेक्टर में नौशहरा नार्द के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान दो आतंकवादी मारे गए। इलाके में अभी तलाशी अभियान चल रहा है।

25 अगस्त को संयुक्त बलों ने बारामूला के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया

इससे पहले, 25 अगस्त को संयुक्त बलों ने बारामूला के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया। उरी सेक्टर के तोरणा इलाके में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जब नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी।

घुसपैठियों को चुनौती दी गई, जिसके बाद दोनों ओर से कुछ देर तक गोलीबारी हुई

घुसपैठियों को चुनौती दी गई, जिसके बाद दोनों ओर से कुछ देर तक गोलीबारी हुई। इसके बाद इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी आतंकवादी नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय सीमा में घुसने में कामयाब न हो पाए। वहीं, 13 अगस्त को उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सेना के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया था, जब आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे।

जम्मू-कश्मीर में संयुक्त बलों ने आतंकियों, उनके सहयोगियों और समर्थकों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है

जम्मू-कश्मीर में संयुक्त बलों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू किए हैं, जिसमें आतंकियों, उनके सहयोगियों (ओजीडब्ल्यू) और समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। इन अभियानों का मकसद केवल हथियारबंद आतंकियों को खत्म करना नहीं, बल्कि पूरे आतंकी तंत्र को ध्वस्त करना है।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नियमित रूप से सुरक्षा समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, जिसमें उनका ध्यान आतंकवाद के पूरे ढांचे को तोड़ने पर है

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नियमित रूप से सुरक्षा समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, जिसमें उनका ध्यान आतंकवाद के पूरे ढांचे को तोड़ने पर है। हवाला धन रैकेट, ड्रग तस्करी और नशीली दवाओं के कारोबार पर भी संयुक्त बलों की कड़ी नजर है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इनसे मिलने वाला पैसा आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस्तेमाल होता है।

खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने कई हवाला रैकेट और ड्रग तस्करी के नेटवर्क को पकड़ा है, जिनके तार सीमा पार बैठे आतंकी सरगनाओं से जुड़े थे

खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने कई हवाला रैकेट और ड्रग तस्करी के नेटवर्क को पकड़ा है, जिनके तार सीमा पार बैठे आतंकी सरगनाओं से जुड़े थे। इसीलिए संयुक्त बल हवाला रैकेट और ड्रग तस्करी जैसी गतिविधियों को प्राथमिकता के साथ निशाना बना रहे हैं, साथ ही हथियारों का इस्तेमाल करने वाले आतंकियों से भी निपट रहे हैं।

जीएसटी सुधार से टैरिफ का असर घटेगा

-भारत बनी रहेगी सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली (एजेंसी)। फिच सॉल्यूशंस की सहायक कंपनी बीएमआई ने गुरुवार को कहा कि आगामी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार, जिनका उद्देश्य दरों में कटौती और निजी खपत को बढ़ावा देना है, अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम कर सकते हैं। साथ ही, कंपनी ने यह भी कहा कि भारत इस दशक में एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा।

बीएमआई के नोट के अनुसार, भारत की जीडीपी 6 प्रतिशत से ऊपर रहने का अनुमान है

बीएमआई के नोट के अनुसार, भारत की जीडीपी 6 प्रतिशत से ऊपर रहने का अनुमान है, भले ही अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ कुछ उद्योगों को प्रभावित कर रहे हों। बीएमआई ने कहा, "हमारा अनुमान है कि दशक के अंत तक भारत की आर्थिक वृद्धि दर धीरे-धीरे धीमी होकर 6.0 प्रतिशत से थोड़ी अधिक हो जाएगी, जो 2010-2019 के महामारी-पूर्व औसत 6.5 प्रतिशत से थोड़ा कम है, फिर भी भारत एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा।"

आने वाले दशक में उत्पादकता में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जिससे जीडीपी वृद्धि को पर्याप्त गति मिलेगी

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आने वाले दशक में उत्पादकता में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जिससे जीडीपी वृद्धि को पर्याप्त गति मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार "हमने पहले अनुमान लगाया था कि 'रेसिप्रोकल' टैरिफ में 25 प्रतिशत की वृद्धि वित्त वर्ष 2025/26 (अप्रैल-मार्च) और वित्त वर्ष 2026/27 में रियल जीडीपी वृद्धि को 0.2 प्रतिशत और धीमा कर देगी। इसलिए, हमने अपने पूर्वानुमानों को तदनुसार संशोधित किया है और अब उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025/26 में अर्थव्यवस्था 5.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026/27 में 5.4 प्रतिशत बढ़ेगी।"

विशिष्टताओं के आधार पर, 'जीएसटी सुधार' टैरिफ से विकास पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकता है

जीएसटी सुधारों पर बीएमआई ने कहा, "विशिष्टताओं के आधार पर, 'जीएसटी सुधार' टैरिफ से विकास पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकता है। क्योंकि डिटेल्स की अभी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हम जीएसटी सुधार को फिलहाल हमारे विकास पूर्वानुमान के लिए एक मामूली वृद्धि जोखिम के रूप में देखते हैं।"

आगामी दो-स्लैब जीएसटी रेशनलाइजेशन से ऑटो, फाइनेंस, सीमेंट व उपभोक्ता वस्तुओं की खपत और लाभप्रदता बढ़ने की उम्मीद है

दो-स्लैब टैक्स स्ट्रक्चर के आगामी जीएसटी स्लैब रेशनलाइजेशन से ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विस, सीमेंट और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में खपत बढ़ने और लाभप्रदता में सुधार होने की उम्मीद है। एसबीआई रिसर्च की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी सुधारों और हाल ही में आयकर में की गई कटौती से उपभोग में 5.31 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकती है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 1.6 प्रतिशत के बराबर है।फिच रेटिंग्स ने भी भारत की रेटिंग को स्टेबल आउटलुक के साथ 'बीबीबी' पर बरकरार रखा है और अनुमान लगाया है कि अमेरिकी टैरिफ का विकास पर सीमित प्रभाव पड़ेगा।

उत्तर भारत में तबाही: पंजाब, जम्मू और हिमाचल में बारिश-बाढ़ से हाहाकार

चंडीगढ़/जम्मू/शिमला (एजेंसी)। उत्तर भारत में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने हालात बेहद ख़राब कर दिए हैं। पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। कई जिलों में सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत-बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।

पंजाब में 7 जिले डूबे, 150 गांव प्रभावित

पंजाब में रावी, ब्यास और सतलुज नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर है। नतीजतन 7 जिले और 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राज्य सरकार ने 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है।

अजनाला में सेना की एम्फीबियस गाड़ियां तैनात की गई हैं, जो पानी और जमीन दोनों पर चल सकती हैं।

इन गाड़ियों की मदद से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

जम्मू में 27 जवान फंसे, 10 घंटे बाद बचाव

जम्मू-कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है।

जम्मू के जौरियन इलाके में 27 जवान पानी में फंस गए थे।

सेना की व्हाइट नाइट कोर टीम ने 10 घंटे चले ऑपरेशन में सभी जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला।

हिमाचल में हाईवे बंद, घरों में मलबा

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने कहर ढा दिया है।

चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर कई जगह भारी भूस्खलन हुआ है।

चंबा जिले में कई घरों के अंदर मलबा घुस गया है।

राज्य के 3 जिलों में 2000 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हैं।

अब तक का नुकसान

310 लोगों की मौत

369 लोग घायल

38 लोग लापता

1240 से ज्यादा घरों को नुकसान

इनमें से 331 घर पूरी तरह से ढह गए हैं।

सरकार ने प्रभावित जिलों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। एनडीआरएफ और सेना की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है।

देहरादून-हैदराबाद फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग

जयपुर। देहरादून से हैदराबाद जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E-423 को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने स्थिति को देखते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी और फ्लाइट को गुरुवार शाम 7:28 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया।इंडिगो के इंजीनियर फिलहाल विमान की खराबी को दुरुस्त करने में जुटे हैं, वहीं यात्री जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान हैं। इसी बीच, अहमदाबाद में खराब मौसम के चलते दो फ्लाइट्स — अकासा एयर (पुणे-अहमदाबाद) और एयर इंडिया (मुंबई-अहमदाबाद) — को भी डायवर्ट कर जयपुर एयरपोर्ट लाया गया।

हरियाणा की महिलाओं को बड़ी सौगात

-हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए, 25 सितंबर से शुरू होगी योजना

हरियाणा (एजेंसी)। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा एलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा की कि राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का नाम 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' रखा गया है और इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2025 को दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर होगी। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि योजना के पहले चरण में उन परिवारों की महिलाएं शामिल होंगी जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। बाद में धीरे-धीरे अन्य परिवारों की महिलाओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा। योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 23 साल या उससे अधिक है। इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों शामिल होंगी, लेकिन शर्त यह है कि महिला पिछले 15 साल से हरियाणा की स्थायी निवासी हो।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। अगर एक परिवार में तीन महिलाएं पात्र हैं, तो तीनों को यह लाभ मिलेगा। लेकिन यदि किसी महिला को पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत 2100 रुपए से ज्यादा की राशि मिल रही है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, स्टेज-3 और स्टेज-4 कैंसर पीड़ित महिलाओं और 54 दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को अगर पहले से पेंशन मिल रही है, तो उन्हें इस योजना का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। राज्य सरकार का अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19 से 20 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। अगले सात दिनों में योजना का गजट नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा।

रॉयल पत्रिका

संपादकीय....

अमेरीका के टैरिफ दबाव के बावजूद राष्ट्रीय हित सर्वोपरि

भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते का मसला इस समय बेहद संवेदनशील मोड़ पर है। अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लागू करने की घोषणा ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को नया तनाव दे दिया है। इससे पहले ही भारत पर कुल 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया जा चुका है और अब यदि यह नया बोझ लागू होता है तो भारतीय निर्यातकों और उद्योगों पर इसका गहरा असर पड़ना तय है। इसके बावजूद भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी नीतियों का आधार केवल राष्ट्रीय हित होंगे, न कि किसी दूसरे देश का दबाव या दबाव की राजनीति। विदेश मंत्री एस. जयशंकर का यह बयान सिर्फ अमरीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि भारत अब एक आत्मविश्वासी राष्ट्र है, जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक नीतियों पर अडिग है। भारत की इस स्पष्टवादी नीति का अर्थ है कि वह अमरीका के टैरिफ दबाव के बावजूद अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। भारतीय विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि किसानों, छोटे उत्पादकों और राष्ट्रीय स्वायत्तता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। दरअसल, अमरीका का यह मान लेना कि भारत को केवल व्यापारिक दबाव डालकर अपनी नीतियाँ बदलने पर मजबूर किया जा सकता है, एक गंभीर गलतफहमी है। भारत अब 21वीं सदी में उस दौर में पहुंच चुका है जहां वह न केवल दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है बल्कि वैश्विक राजनीति में भी निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है। भारत का यह रुख यह भी दर्शाता है कि वह केवल अपने निर्यात या अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए अपनी नीतियों को कमजोर नहीं करेगा। किसान और छोटे उत्पादक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यदि अमरीका के साथ समझौते के नाम पर उनके हितों को नुकसान पहुँचता है तो इसका असर सीधा भारत की आंतरिक स्थिरता और सामाजिक ढांचे पर पड़ेगा। यही कारण है कि भारत ने 'लक्ष्मण रेखा' खींचते हुए साफ कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में वह अपने नागरिकों और उद्योगों को नुकसान नहीं होने देगा। भारत की यह सख्त भाषा केवल अमरीका को संदेश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकसित कहे जाने वाले सभी देशों के लिए एक चेतावनी है। दशकों तक पश्चिमी देश अपनी नीतियां छोटे और विकासशील देशों पर थोपते रहे हैं। वे यह मानकर चलते रहे कि आर्थिक मदद, व्यापारिक साझेदारी या सामरिक सहयोग के नाम पर वे दूसरे देशों को अपने एजेंडे के अनुसार झुका सकते हैं। लेकिन आज भारत जैसे देशों की स्थिति बदल चुकी है। भारत अब उस कतार में खड़ा है, जहां वह न केवल बराबरी का दर्जा चाहता है, बल्कि हर मसले पर अपनी बात मजबूती से रखने की ताकत भी रखता है। भारत-अमरीका के संबंध लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग पर टिके रहे हैं। लेकिन इस रिश्ते की नींव तभी मजबूत रह सकती है जब दोनों देशों के बीच बराबरी और आपसी सम्मान कायम रहे।

ट्रंप की नीति: संघीय हस्तक्षेप बनाम अमेरिकी लोकतंत्र पर संकट

-ट्रंप की नीति: कानून व्यवस्था या राजनीतिक एजेंडा?

अमेरिका, जिसे अक्सर आधुनिक लोकतंत्र का आदर्श माना जाता है, आज अपने ही संविधान और संघीय ढांचे की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हाल ही में दिए गया बयान—कि वे वाशिंगटन डीसी के बाद अब शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में भी नेशनल गार्ड की तैनाती करेंगे—सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह संघीय व्यवस्था पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। ट्रंप का तर्क है कि ये शहर कानूनहीनता और अपराधियों का अड्डा बन चुके हैं और जब स्थानीय सरकारें असफल हो जाती हैं तो संघीय सत्ता को हस्तक्षेप करना पड़ता है। परंतु सवाल यह है कि क्या वास्तव में ऐसा है? या फिर यह कदम अमेरिकी लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाने वाला राजनीतिक दांव है?

अमेरिकी संघीय ढांचे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अमेरिका का संविधान 1787 में अस्तित्व में आया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह "फेडरलिज्म" यानी संघीय ढांचे पर आधारित है। इसका मतलब है कि शक्ति का विभाजन राज्यों और केंद्र (संघीय सरकार) के बीच बराबरी से किया गया है। राज्यों की स्वायत्तता: कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग का अधिकार राज्यों और स्थानीय सरकारों के पास है। संघीय भूमिका: संघीय सरकार आमतौर पर रक्षा, विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय स्तर की नीतियों के लिए जिम्मेदार होती है। संविधान का संतुलन: संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सत्ता, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, दूसरी सत्ता पर हावी न हो। इसी संघीय संरचना के कारण अमेरिका में स्थानीय लोकतंत्र को ताकत मिली और अलग-अलग राज्यों की पहचान और स्वतंत्रता बनी रही।

ट्रंप की नीति: कानून व्यवस्था बनाम राजनीतिक एजेंडा

ट्रंप का दावा है कि डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहर अपराध और हिंसा के अड्डे बन चुके हैं। उनका कहना है कि जब स्थानीय सरकारें नागरिकों की सुरक्षा करने में विफल होती हैं, तो संघीय सत्ता का हस्तक्षेप आवश्यक है। लेकिन यह तर्क कई स्तरों पर सवालों के घेरे में है— आंकड़े झूठ नहीं बोलते: 2025 के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे शहरों में अपराध की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। शिकागो में हत्या और गोलीबारी की घटनाओं में दो अंकीय गिरावट दर्ज की गई है। न्यूयॉर्क, जिसे कभी "क्राइम कैपिटल" कहा जाता था, वहां हिंसक अपराध 15% कम हुए हैं। यानी अपराध बढ़ने का ट्रंप का तर्क वास्तविकता पर आधारित नहीं है।

राजनीतिक टकराव: डेमोक्रेटिक पार्टी इन शहरों में शासन करती है। ट्रंप का कदम प्रत्यक्ष रूप से उनकी सत्ता को चुनौती देता है और स्थानीय निकायों की स्वायत्तता को कमजोर करता है।

संवैधानिक उल्लंघन: संविधान के तहत स्थानीय पुलिस पर नियंत्रण राज्यों और नगर प्रशासन का अधिकार है। राष्ट्रपति द्वारा सीधे नेशनल गार्ड की तैनाती, खासकर बिना राज्य सरकार की सहमति के, संविधान के संघीय सिद्धांतों पर सीधा हमला है।

वाशिंगटन डीसी से शिकागो और न्यूयॉर्क तक

वाशिंगटन डीसी: ट्रंप ने सबसे पहले राजधानी वाशिंगटन में स्थानीय पुलिस की शक्तियों को सीमित किया और नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी। उन्होंने "सुरक्षा" के नाम पर संघीय एजेंसियों को सीधा हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया। शिकागो और न्यूयॉर्क: अब ट्रंप ने इन्हीं नीतियों को शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे बड़े डेमोक्रेटिक शहरों में लागू करने की चेतावनी दी है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन संघीय सत्ता इसे थोपने पर आमादा है। यह कदम केवल कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है।

डेमोक्रेटिक प्रतिक्रिया

डेमोक्रेट नेताओं का कहना है कि ट्रंप अपराध को बहाना बना कर सत्ता केंद्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर का बयान: "हमारी पुलिस व्यवस्था पहले से ही मजबूत है। हमें संघीय हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं। यह कदम लोकतंत्र को कमजोर करेगा।" शिकागो की मेयर: "यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है।" डेमोक्रेटिक पार्टी का आरोप है कि ट्रंप आगामी चुनावों को देखते हुए "कानून और व्यवस्था" का मुद्दा उठाकर जनता की भावनाओं को प्रभावित करना चाहते हैं।

रिपब्लिकन रणनीति: "लॉ एंड ऑर्डर" पॉलिटिक्स

रिपब्लिकन पार्टी लंबे समय से "लॉ एंड ऑर्डर" यानी कानून और व्यवस्था को अपनी चुनावी रणनीति का केंद्र बनाती रही है। ट्रंप भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता: रिपब्लिकन यह तर्क देते हैं कि सुरक्षा और स्थिरता सबसे बड़ा मुद्दा है, भले ही इसके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं या राज्यों की स्वायत्तता से समझौता करना पड़े। डर की राजनीति: ट्रंप ने "कानूनहीन गिरोहों" और "अपराधी प्रवृत्तियों" का मुद्दा उठाकर समाज में डर का माहौल बनाया। चुनावी फायदा: यह रणनीति खासकर उपनगरों और ग्रामीण इलाकों में काम करती है, जहां लोग शहरों की अपराध छवि से पहले ही आशंकित रहते हैं।

संवैधानिक संकट की आहट

ट्रंप की यह नीति अमेरिका में संवैधानिक संकट की ओर इशारा करती है। शक्ति संतुलन का संकट: संविधान में शक्ति का बंटवारा स्पष्ट है। अगर राष्ट्रपति राज्यों की सहमति के बिना उनकी पुलिस व्यवस्था में हस्तक्षेप करेंगे, तो यह शक्ति संतुलन बिगाड़ देगा। न्यायपालिका की भूमिका: इस मुद्दे पर अदालतों का दखल अनिवार्य होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहराया, तो ट्रंप की नीतियां रद्द हो सकती हैं। लोकतांत्रिक परंपराओं पर प्रहार: अमेरिकी लोकतंत्र हमेशा "विकेंद्रीकरण" और "लोकल गवर्नेंस" का समर्थक रहा है। ट्रंप का कदम इन परंपराओं को कमजोर करता है।

अंतरराष्ट्रीय नजरिया

अमेरिका को पूरी दुनिया लोकतंत्र के आदर्श के रूप में देखती है। यदि वहां राष्ट्रपति राज्यों की स्वायत्तता पर हमला करते हैं, तो यह संदेश दुनिया के अन्य लोकतंत्रों के लिए खतरनाक होगा। चीन और रूस जैसे देश: वे कह सकते हैं कि अमेरिका भी उसी तरह केंद्रीकरण करता है जैसे वे करते हैं। भारत जैसे लोकतंत्र: जहां पहले से ही केंद्र और राज्यों के बीच टकराव होते रहते हैं, वहां अमेरिकी घटनाक्रम से गलत उदाहरण सामने आ सकता है। वैश्विक लोकतंत्र की विश्वसनीयता: अमेरिका की साख कमजोर होगी। अपराध बनाम राजनीति नैरेटिव आंकड़े बताते हैं कि अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप का नैरेटिव अपराध बढ़ने का है। यह विरोधाभास बताता है कि मुद्दा अपराध नहीं, बल्कि सत्ता और राजनीति है। शिकागो: हत्या और गोलीबारी की घटनाएं पिछले साल की तुलना में 12% कम हुई हैं। न्यूयॉर्क: 15% गिरावट दर्ज की गई है। लॉस एंजेलिस: हिंसक अपराध में 9% की कमी आई है। फिर भी ट्रंप इन्हें "कानूनहीन शहर" बताते हैं। यह दर्शाता है कि तथ्य से अधिक राजनीतिक एजेंडा हावी है।

मीडिया की भूमिका

अमेरिकी मीडिया इस पूरे विवाद को दो ध्रुवों में बांट रहा है। लिबरल मीडिया (CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट): वे इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। कंजर्वेटिव मीडिया (Fox News, Breitbart): वे इसे कानून व्यवस्था की बहाली और नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक बता रहे हैं। मीडिया की यह ध्रुवीयता अमेरिकी जनता को और ज्यादा बांट रही है।

जनता की प्रतिक्रिया

जनता भी दो हिस्सों में बंटी है— समर्थक: ट्रंप के समर्थक मानते हैं कि अपराध का असली आंकड़ा छिपाया जा रहा है और संघीय हस्तक्षेप ज़रूरी है। विरोधी: विरोधी मानते हैं कि यह लोकतंत्र का गला घोंटने की दिशा में एक कदम है।

भविष्य के लिए निहितार्थ

लोकतांत्रिक परंपराओं पर खतरा: अगर यह परंपरा स्थापित हो गई कि राष्ट्रपति राज्यों की अनुमति के बिना पुलिस तैनात कर सकते हैं, तो भविष्य में कोई भी राष्ट्रपति इसका दुरुपयोग कर सकता है। राजनीतिक ध्रुवीकरण: अमेरिका पहले से ही गहरे राजनीतिक ध्रुवीकरण से गुजर रहा है। यह कदम उसे और गहरा करेगा। संवैधानिक संकट: अदालतों में लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चलेगी, जिससे प्रशासनिक संकट बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं हैं। यह कदम अमेरिकी लोकतंत्र और संघीय ढांचे दोनों के लिए गंभीर खतरा है। शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में नेशनल गार्ड की तैनाती की धमकी सिर्फ राजनीतिक टकराव नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा पर प्रहार है।

नागरिक अधिकार और वीआईपी दौरे: सुरक्षा, प्रोटोकॉल और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण की ज़रूरत

-सुरक्षा और प्रोटोकॉल की अनिवार्यता

लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार यह है कि जनता सर्वोपरि होती है। चुने हुए प्रतिनिधि और अधिकारी जनता की सेवा के लिए होते हैं, न कि जनता उनके लिए। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी कोई बड़ा नेता, वरिष्ठ अधिकारी या विदेशी मेहमान किसी स्थान पर दौरे पर आता है, तो आम जनता को कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। सड़कों पर भारी-भरकम सुरक्षा इंतज़ाम किए जाते हैं, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, रूट डायवर्जन किए जाते हैं और कभी-कभी तो पूरी सड़क बंद कर दी जाती है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोती गांव में बादल फटने की घटना ने एक बार फिर इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया। यहाँ लगभग 30 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लापता हो गए। राहत और बचाव कार्य चल ही रहे थे कि अचानक वीआईपी दौरे की तैयारियों ने स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवारों की दिक्कतें और बढ़ा दीं। पीड़ितों ने सवाल उठाया कि क्या इस समय नेताओं के लिए विशेष इंतजाम अधिक ज़रूरी हैं या प्रभावित नागरिकों को तुरंत राहत पहुँचाना? यह सवाल केवल एक घटना से जुड़ा नहीं है बल्कि यह उस व्यापक प्रवृत्ति को उजागर करता है, जिसमें नागरिक अधिकार और मानवीय प्राथमिकताएँ अक्सर वीआईपी संस्कृति और सुरक्षा प्रोटोकॉल के आगे दब जाती हैं।

वीआईपी संस्कृति और उसकी जड़ें

भारत में "वीआईपी संस्कृति" (VIP Culture) कोई नया विषय नहीं है। अंग्रेज़ी शासनकाल से ही शासकों और उच्च अधिकारियों के लिए अलग-अलग इंतजाम किए जाते रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद भी यह परंपरा जारी रही और धीरे-धीरे यह हमारे प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा बन गई। बड़े नेताओं के काफ़िले के गुजरते ही पूरे इलाके को बंद कर दिया जाना। ट्रैफिक रोककर आम जनता को घंटों खड़ा रखना। अस्पतालों और स्कूलों के कार्यक्रम रोककर मेहमानों के स्वागत की तैयारी करना। रेस्क्यू या राहत कार्यों के बीच में दौरे की औपचारिकता निभाना। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि व्यवस्था का झुकाव अब भी "ऊपर" की ओर ज़्यादा है, जबकि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत "नीचे" यानी जनता को केंद्र में रखना है।

सुरक्षा और प्रोटोकॉल की अनिवार्यता

यह भी सच है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या विदेश से आने वाले बड़े मेहमानों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण होती है। भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में सुरक्षा की चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। आतंकी खतरे, भीड़-प्रबंधन, संभावित विरोध प्रदर्शन और आकस्मिक घटनाएँ इन दौरों को संवेदनशील बना देती हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियाँ तर्क देती हैं कि – रूट क्लियरेंस इसलिए जरूरी है ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बैरिकेड्स और ट्रैफिक रोकना सुरक्षा घेरा बनाने का हिस्सा है। अचानक भीड़ या अव्यवस्था से बचने के लिए सख्त इंतज़ाम किए जाते हैं। इन तर्कों को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हाल के दशकों में हमने कई ऐसी घटनाएँ देखी हैं, जहाँ सुरक्षा चूक के गंभीर नतीजे सामने आए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुरक्षा इंतज़ाम हमेशा नागरिक जीवन को अस्त-व्यस्त किए बिना नहीं किए जा सकते?

नागरिक अधिकार और असुविधा का मुद्दा

भारतीय संविधान नागरिकों को आवागमन की स्वतंत्रता, जीवन और आजीविका के अधिकार, तथा समानता का अधिकार देता है। जब किसी वीआईपी दौरे के कारण— आम आदमी समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाता, एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है, स्कूल जाने वाले बच्चे देर तक ट्रैफिक जाम में फँस जाते हैं, किसी पीड़ित परिवार को राहत सामग्री मिलने में देरी हो जाती है, तो यह केवल प्रशासनिक असुविधा नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण भी बन जाता है। चशोती में राहत कार्यों के दौरान लोगों ने साफ कहा कि अधिकारियों और नेताओं के लिए बनाए गए इंतजामों से बचाव कार्य की गति धीमी पड़ गई। पीड़ितों ने पूछा कि क्या इस समय प्राथमिकता नेताओं को दिखाना है या पीड़ितों की मदद करना?

आपदा प्रबंधन में वीआईपी दौरे: जरूरत या दिखावा? किसी आपदा स्थल पर वीआईपी दौरे के दो पक्ष हैं:

दौरे के पक्ष में तर्क

नेताओं की मौजूदगी से प्रशासनिक तंत्र सक्रिय हो जाता है। उच्च स्तर पर तुरंत निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। दौरे से पीड़ितों को संदेश जाता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। मीडिया कवरेज से घटना पर ध्यान जाता है और बाहरी मदद जुट सकती है।

दौरे के खिलाफ तर्क

राहत और बचाव कार्यों में बाधा आती है। स्थानीय प्रशासन ध्यान बंटाकर वीआईपी स्वागत और सुरक्षा में लग जाता है। आम जनता को और अधिक असुविधा झेलनी पड़ती है। कई बार दौरे केवल "राजनीतिक दिखावे" और "फोटो सेशन" तक सीमित रह जाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय उदाहरण

दुनिया के कई देशों में ऐसे मामले सामने आते हैं, जहाँ नेताओं के दौरे को लेकर जनता में नाराज़गी दिखी। अमेरिका में राष्ट्रपति के दौरे बेहद सख्त सुरक्षा घेरे में होते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस तरह प्रबंधन करता है कि नागरिकों की दिनचर्या पर न्यूनतम असर पड़े। जापान और यूरोप के कई देशों में नेताओं का दौरा बिना बड़े काफ़िले और दिखावे के होता है। वे आम जनता के बीच भी साधारण सुरक्षा व्यवस्था के साथ पहुँचते हैं। वहीं कई अफ्रीकी और एशियाई देशों में "वीआईपी संस्कृति" भारत जैसी ही गहराई से जमी है। भारत को इन उदाहरणों से सीख लेने की ज़रूरत है कि सुरक्षा और नागरिक सुविधा में संतुलन कैसे बनाया जाए।

नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता

यदि हम लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखना चाहते हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि जनता केंद्र में है और वीआईपी सहित पूरा तंत्र जनता के लिए है। इसके लिए कुछ सुधार जरूरी हैं: वर्चुअल मीटिंग्स और डिजिटल समीक्षा: आपदा या राहत कार्यों की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए हमेशा मौके पर जाना जरूरी नहीं है। आधुनिक तकनीक से लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ड्रोन फुटेज से भी स्थिति समझी जा सकती है। साधारण और सीमित प्रोटोकॉल: वीआईपी दौरे के दौरान जरूरत से ज्यादा सुरक्षा और शोभा टालनी चाहिए। काफ़िला छोटा और व्यावहारिक होना चाहिए। जनता को न्यूनतम असुविधा: ट्रैफिक डायवर्जन या सड़क बंद करने से पहले नागरिकों के अधिकार और सुविधाएँ ध्यान में रखी जानी चाहिए।

हकीम अजमल ख़ान (1868–1927): तिब्बी दुनिया के बादशाह और स्वतंत्रता संग्राम के सच्चे सिपाही

भारत की आज़ादी की जद्दोजहद में जिस तरह बड़े-बड़े राजनेताओं, विद्वानों और क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया, उसी तरह कुछ ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने अपनी विद्वता और समाजसेवा के बल पर राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। इन ही महान विभूतियों में एक थे हकीम अजमल ख़ान। वे न केवल भारत के मशहूर यूनानी चिकित्सक थे बल्कि एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी और जननेता भी थे। उन्होंने ख़िलाफ़त आंदोलन, असहयोग आंदोलन और कांग्रेस के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें उनकी तिब्बी सेवा और राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व के कारण "मसीहा-ए-हिंद" कहा जाता है।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

हकीम अजमल ख़ान का जन्म 11 फरवरी 1868 को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित तिब्बी (यूनानी चिकित्सा) परिवार में हुआ। उनका परिवार "शाही हकीमों" का परिवार माना जाता था। उनके दादा और पिता मुग़ल दरबार में हकीम रहे थे। परिवार में चिकित्सा और इल्म (ज्ञान) की परंपरा गहरी थी। छोटी उम्र से ही अजमल ख़ान का रुझान इल्म और तिब्ब (चिकित्सा) की तरफ था। उन्होंने अरबी, फ़ारसी और यूनानी तिब्ब की उच्च शिक्षा प्राप्त की। चूंकि उनका घर ही तिब्ब का बड़ा केंद्र था, इसलिए बचपन से ही उन्हें दवाइयों, नुस्ख़ों और इलाज का गहरा अनुभव मिला।

तिब्बी (यूनानी चिकित्सा) में योगदान

हकीम अजमल ख़ान ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली में गहरा योगदान दिया। यूनानी तिब्ब के संरक्षक – उन्होंने यूनानी पद्धति को न केवल जीवित रखा बल्कि उसे आधुनिक रूप भी दिया। तिब्बी कॉलेज और संस्थान – उनके प्रयास से दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज (1916) की स्थापना हुई। यह कॉलेज आज भी उनके नाम पर "अजमल ख़ान तिब्बिया कॉलेज" के रूप में मशहूर है। इलाज और दानशीलता – वे गरीबों का मुफ़्त इलाज करते थे। उनके यहाँ रोज़ सैकड़ों मरीज़ आते थे और वे बिना किसी लालच के सबका इलाज करते थे। अनुसंधान और शिक्षा – उन्होंने यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की कोशिश की। उनकी पहचान केवल एक हकीम की नहीं थी बल्कि एक ऐसे समाज सुधारक की थी, जो चाहता था कि भारतीय चिकित्सा और ज्ञान की परंपराएं नष्ट न हों बल्कि आगे बढ़ें।

सामाजिक और शैक्षिक योगदान

हकीम अजमल ख़ान ने तिब्ब के अलावा शिक्षा और समाज सुधार में भी गहरी रुचि ली। उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। यह संस्थान आज भी उनकी दूरदृष्टि का प्रमाण है। वे अलीगढ़ आंदोलन और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भी समर्थक रहे। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया।

स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश

हकीम अजमल ख़ान का असली मक़सद सिर्फ़ हकीम रहना नहीं था। उन्हें मुल्क की गुलामी बहुत खलती थी। धीरे-धीरे उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया और पूरे देश में गुस्सा फैला, तब वे खुलकर आंदोलन में उतरे। उनकी लोकप्रियता केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं थी बल्कि हिन्दू समाज में भी उनका सम्मान था।

ख़िलाफ़त आंदोलन में भूमिका

ख़िलाफ़त आंदोलन (1919–1924) भारत के इतिहास का अहम हिस्सा है। यह आंदोलन तुर्की में ख़िलाफ़त की रक्षा के नाम पर शुरू हुआ था, लेकिन भारत में इसने आज़ादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी। हकीम अजमल ख़ान इस आंदोलन के बड़े नेताओं में से थे। उन्होंने महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अली बंधुओं (शौकत अली और मोहम्मद अली) के साथ मिलकर इसे मज़बूत किया। इस आंदोलन के ज़रिए उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता को और मजबूत किया। गांधीजी भी उन्हें बहुत सम्मान देते थे। ख़िलाफ़त आंदोलन ने भारत में आज़ादी की लड़ाई को जन-आंदोलन का रूप देने में अहम भूमिका निभाई और हकीम अजमल ख़ान इसकी धड़कन बने।

असहयोग आंदोलन में नेतृत्व

महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में हकीम अजमल ख़ान की सक्रिय भूमिका रही। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, सरकारी नौकरियों से इस्तीफ़ा और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान बनाने की मुहिम का समर्थन किया। दिल्ली और उत्तर भारत में उन्होंने इस आंदोलन को नई ऊर्जा दी। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता का पैग़ाम दिया और कहा कि "आजादी सिर्फ़ मिलकर ही हासिल की जा सकती है।"

कांग्रेस में स्थान और नेतृत्व

हकीम अजमल ख़ान की लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए कांग्रेस ने भी उन्हें बड़ी ज़िम्मेदारियाँ दीं। वे 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उनका अध्यक्ष बनना इस बात का सबूत था कि कांग्रेस हिन्दू-मुस्लिम एकता की हक़ीक़ी तस्वीर है। वे उन गिने-चुने नेताओं में थे, जिन्हें गांधीजी, मौलाना आज़ाद, गोखले और जिन्ना – सभी बराबर सम्मान देते थे।

हिन्दू-मुस्लिम एकता के सिपाही

हकीम अजमल ख़ान ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया कि मुल्क की आज़ादी तभी संभव है जब हिन्दू और मुसलमान एक होकर लड़ें। वे धार्मिक उग्रवाद के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने हमेशा साझा संस्कृति और साझा आंदोलन का समर्थन किया। उनके भाषण और लेखन में यह साफ़ दिखता है कि वे भारत को सिर्फ़ मुसलमानों या हिन्दुओं का नहीं बल्कि सबका मुल्क मानते थे।

व्यक्तिगत जीवन और सादगी

हकीम अजमल ख़ान बहुत सादगीपसंद इंसान थे। वे साधारण कपड़े पहनते और गरीबों की मदद करना अपना फ़र्ज़ समझते। वे कभी लालच या सत्ता की राजनीति में नहीं फंसे। उनका जीवन सेवा, इबादत और क़ौम के लिए कुर्बानी की मिसाल था।

निधन

29 दिसंबर 1927 को हकीम अजमल ख़ान का इंतक़ाल हो गया। उनकी मौत से देश ने न सिर्फ़ एक महान हकीम को खोया बल्कि एक ऐसे राष्ट्रीय नेता को भी, जिसने आज़ादी के आंदोलन को नई दिशा दी थी। उनकी मृत्यु पर गांधीजी और मौलाना आज़ाद जैसे बड़े नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया।

विरासत

हकीम अजमल ख़ान आज भी भारतीय इतिहास में एक प्रेरणा हैं। तिब्बिया कॉलेज और जामिया मिल्लिया इस्लामिया उनकी दूरदृष्टि के जीवंत स्मारक हैं। उनका नाम हिन्दू-मुस्लिम एकता, सेवा और आज़ादी की जद्दोजहद के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। वे इस बात की मिसाल हैं कि एक डॉक्टर, एक शिक्षक और एक समाजसेवी भी आज़ादी का सिपाही बन सकता है।

निवेश और औद्योगिक क्षेत्र में राज्य ने रचा नया इतिहास

-बिजली-पानी-रोजगार क्षेत्र में ले रहे अभूतपूर्व निर्णय - भजनलाल शर्मा

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि समृद्ध, सशक्त और सर्वोपरि राज्य बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि उद्यमी अधिक से अधिक निवेश कर राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनें।

शर्मा गुरूवार को जयपुर में इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा तथा व्यापारिक दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन से राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, इनमें से 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर धरातल पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को अधिक सुगम बनाने के लिए राज्य में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान मिनरल पॉलिसी, रीको प्रत्यक्ष आवंटन नीति, डेटा सेंटर नीति, वस्त्र एवं परिधान नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति जैसी नीतियां जारी की गई।

विजन डॉक्यूमेंट-2047 राजस्थान के सुनहरे भविष्य का खाका-

शर्मा ने कहा कि राजस्थान ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी में देशभर में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश के कुल खनिज ब्लॉक आवंटन का 20 प्रतिशत अकेले राजस्थान से हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने विजन डॉक्यूमेंट-2047 को मंजूरी दी है। यह केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि राजस्थान के सुनहरे भविष्य का खाका है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक राजस्थान 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 सौर परियोजनाओं को मंजूरी, नई भूमि आवंटन नीति, पंच गौरव जैसे नवाचारों एवं निर्णयों से ऊर्जा एवं उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

जोधपुर-पाली औद्योगिक गलियारा विकास का एक नया अध्याय-

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। जोधपुर-पाली औद्योगिक गलियारा, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 19 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 50,000 प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा वस्त्र, कृषि, इंजीनियरिंग और ऑटो क्लस्टर उद्योगों पर केंद्रित यह परियोजना राजस्थान को औद्योगिक मानचित्र पर नया स्थान दिलाएगी।

प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए गए अनेक कदम-

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 जारी की गई है, जो 2030 तक प्रदेश के अक्षय ऊर्जा उत्पादन को 125 गीगावाट के स्तर तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है तथा 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'एक पेड़ मां के नाम अभियान' से प्रेरणा लेते हुए 'हरियालो राजस्थान' की शुरुआत की है। अभियान के तहत 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है तथा अब तक हम 17 करोड़ से अधिक पौधे लगा चुके हैं।

राजस्थान ऑल टाइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन- दिया कुमारी

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने समाचार पत्र 'इकोनॉमिक टाइम्स' की ओर से गुरूवार को जयपुर में आयोजित राजस्थान बिजनेस समिट और पुरस्कार समारोह में कहा कि राजस्थान पर्यटन के विकास में निजी क्षेत्र ने अत्यंत महत्वपूर्ण और शानदार योगदान दिया है। सरकार पर्यटन व्यवसाय नहीं कर सकती अपितु एक फेसिलिटेटर के रूप में काम कर सकती है। सरकार सुविधाओं का विकास कर सकती है, जो किया जा रहा है। सरकार रोड बनवा सकती है, रेल, बस, हवाई सुविधाओं का विकास कर सकती है, जो नियमित रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटक स्थलों के संरक्षण का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विश्व में क्लाइमेट चेंज हुआ है। पहले कहा जाता था कि राजस्थान में ऑफ सीजन मे पर्यटन संभव नहीं है लेकिन इस परसेप्शन को बदलने की आवश्यकता है। राजस्थान में ऑफ सीजन में भी पर्यटन संभव है। राजस्थान ऑल टाइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दिया कुमारी ने पर्यटन विकास की नई संभावनाओं के लिए आमजन का नये विचार, थीम, इनोवेशन के साथ आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन विकास के नये आइडिया को प्रोत्साहित करेगी, साल में कम से कम एक— दो बार आईफा जैसे आयोजन होते रहने चाहिए। राजस्थान में कन्सर्ट टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म की बहुत संभावनाएं है। आज के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर्यटन विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंच हैं। इससे पूर्व पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव तथा आरटीडीसी अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि राज्य में ऐतिहासिक स्मारकों से आगे भी पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सम्भावनाएं हैं, जिन पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में हमारा प्रदेश तेजी से आगे बढ़ते हुए दुनिया के पर्यटन का सिरमौर बन रहा है। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से ट्राइबल ट्यूरिज्म सर्किट पर अच्छा काम किया जा रहा। इसी प्रकार धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, वन्य पर्यटन भी पर्यटन के अत्यंत बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप उभर रहे हैं। राजस्थान का फूड, हेरिटेज, म्यूजिक, फोक कल्चर सब कुछ अलग तरह की संभावनाओं को समाहित किये हुए है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की हवेलियों जैसी अद्त सांस्कृतिक विरासत राजस्थान पर्यटन को

समृद्ध करती है और पर्यटन क्षेत्र में नये द्वारा खोलती है। प्रदेश में पर्यटन के विभिन्न नए क्षेत्र उभर रहें हैं। राजेश यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पर्यटन इकाई नीति— 2024 लागू की गई है जिसमें निवेशकों के लिए कई प्रोत्साहन प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही सरकार दो नई नीतियां लेकर आ रही हैं। यह पहली राजस्थान पर्यटन नीति है जिसमें समग्र पर्यटन अवसंरचना, रोजगार सृजन और अनुभव आधारित पर्यटन पर जोर दिया गया है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति में राजस्थान को एक वैश्विक फिल्म शूटिंग हब बनाये जाने पर कार्य किया जाएगा। पर्यटन आयुक्त श्रीमती रूक्मणि रियार ने पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राजस्थान घरेलू और विदेशी पर्यटकों के मामले में भारत में 5वें स्थान पर है। श्रीमती रियार ने कहा कि राजस्थान पर्यटन की खासियतें इसकी विविधताओं में निहित हैं जिनमें ऐतिहासिक किले, महल, रेगिस्तान, झीलें, वन्यजीव अभ्यारण्य, धार्मिक स्थल और ग्रामीण पर्यटन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान को 'डेस्टिनेशन वेडिंग', 'लक्ज़री टूरिज्म' और 'हेरिटेज टूरिज्म' के लिए सबसे पसंदीदा जगह के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन (MICE) के लिए भी एक केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की खासियत है कि इस राज्य में अपनी विरासत का संरक्षण किया जा रहा है और इस विरासत को सहेजते हुए राजस्थान आज वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

कोटा के मीट व्यापारीयों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नगर निगम का सीलिंग आदेश निरस्त

जयपुर (रॉयल पत्रिका) । राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर खंडपीठ ने बुधवार को कोटा के मीट व्यापारी मोहम्मद सलीम, मोहम्मद उमर और इस्लाम कुरैशी, को बड़ी राहत देते हुए नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा दुकान सील करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति अनूप ढंढ ने सुनाया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजीत कस्वा और अंसार इंदौरी ने प्रभावशाली और तथ्यों पर आधारित जोरदार पैरवी की। मीट व्यापारी मोहम्मद सलीम, मोहम्मद उमर और इस्लाम कुरैशी की दुकानो को नगर निगम ने 17 मार्च 2025 को सील कर दिया था। व्यापारीयों ने पहले नगर निगम आयुक्त व जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी बात रखी, परंतु कोई राहत न मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अधिवक्ता अंसार इंदौरी ने बताया कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि नगर निगम की यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और ग़ैरक़ानूनी तरीके से की गई थी। कोर्ट ने निगम के सीलिंग आदेश को विधिसम्मत नहीं मानते हुए पूरी तरह निरस्त कर दिया। गौरतलब है कि इससे पूर्व 30 मई 2025 को भी हाईकोर्ट ने मीट व्यापारी नदीम अंसारी के पक्ष में फैसला देते हुए ईद के मौके पर कोटा नगर निगम द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने तब भी स्पष्ट किया था कि धार्मिक त्योहारों के समय व्यापारियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कोटा नगर निगम ने बीते कुछ महीनों में कई मीट दुकानों को सील कर दिया था, जिससे स्थानीय व्यापारी वर्ग में भारी असंतोष था। मोहम्मद सलीम,मोहम्मद उमर और इस्लाम कुरैशी, को बड़ी राहत देते हुए नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा दुकान सील करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति अनूप ढंढ ने सुनाया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजीत कस्वा और अंसार इंदौरी ने प्रभावशाली और तथ्यों पर आधारित जोरदार पैरवी की। मीट व्यापारी मोहम्मद सलीम, मोहम्मद उमर और इस्लाम कुरैशी की दुकान भी इसी कार्रवाई की शिकार बनी थी। लेकिन अब हाईकोर्ट के इस निर्णय से न केवल मोहम्मद उमर और इस्लाम कुरैशी, को बड़ी राहत देते हुए नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा दुकान सील करने

के आदेश को निरस्त कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति अनूप ढंढ ने सुनाया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजीत कस्वा और अंसार इंदौरी ने प्रभावशाली और तथ्यों पर आधारित जोरदार पैरवी की। मीट व्यापारी मोहम्मद सलीम, मोहम्मद उमर और इस्लाम कुरैशी को न्याय मिला है, बल्कि अन्य मीट व्यापारियों को भी राहत की उम्मीद जगी है। इस ऐतिहासिक फैसले में न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि प्रशासनिक कार्रवाई करते समय संवैधानिक अधिकारों, विशेषकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और व्यापार करने के मूल अधिकार का सम्मान किया जाना आवश्यक है। वकील अजीत कस्वा और अंसार इंदौरी की इस सफल पैरवी को कानूनी हलकों में महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है।

आधार के दुरूपयोग को रोकने में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका, साइबर फ्रॉड पर लगे अंकुश- मुख्य सचिव

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि प्रदेश में आधार के दुरूपयोग एवं इससे होने वाले साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एआई (अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाल आधार (5 साल तक के बच्चे का आधार) सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए सम्बंधित सभी विभाग आवश्यक कार्यवाही में तेजी लाए एवं लंबित कार्यों को शीघ्र सम्पादित करें।

मुख्य सचिव सुधांश पंत गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित यूआईडी कार्यान्वयन समिति (यूआईडीआईसी) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आधार की विश्वसनीयता को बनाये रखने के लिए तकनीक के इस दौर में एआई का उपयोग कर आधार से सम्बंधित साइबर फ्रॉड को रोका जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक प्रयास करने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में पंत ने बाल नामांकन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही के दिशा निर्देश दिए। उन्होने कहा कि 5 वर्ष तक आयु के बच्चों के आधार नामांकन के लिए प्रदेश में प्री—स्कूल और आंगनबाड़ियों में विशेष अभियान चला कर जागरूकता फैलाई जाए। प्रदेश के सरकारी एवं निजी विद्यालयों को इस सम्बन्ध में निर्देशित कर आधार नामांकन में वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न आईईसी गतिविधियों के माध्यम से इस दिशा में व्यापक प्रचार-प्रसार कर माता-पिता को बाल आधार नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्य सचिव ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन पर भी विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया। पंत ने सम्बंधित विभागों को आधार नामांकन एवं अपडेशन की प्रक्रिया में आवश्यक अन्य दस्तावेजों के भी डिजिटाइजेशन के लिए निर्देश दिए। बैठक में निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली, कुमार उज्ज्वल ने राज्य में आधार सैचुरेशन की स्थिति एवं अन्य आवश्यक विषयों पर चर्चा की । शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, श्रीमती अर्चना सिंह ने इस सम्बन्ध में नोडल विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों एवं प्रगति की जानकारी दी। इस अवसर पर यूआईडीआईसी की गत बैठक में विभागों को दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई। जिसके तहत प्रदेश में अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट, आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन (एएलबीआर), स्टेट वेरिफिकेशन पोर्टल की स्थिति, जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग समिति (डीएलएएमसी) जैसी विषयों की प्रगति की जानकारी साझा की गई। समीक्षा में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं और सुशासन कार्यक्रमों में आधार-सक्षम सेवाओं को भी शामिल किया गया।

33 वीं विशाल पदयात्रा विधिवत पूजा अर्चना के साथ रवाना हुई

मनोहरपुर (रॉयल पत्रिका)। कस्बे के आमलियों का बास स्थिति श्री देवनारायण भगवान के मंदिर परिसर से 33 वीं विशाल पदयात्रा विधिवत पूजा अर्चना के साथ रवाना हुई। यात्रा आमलियों का बास देव नारायण भगवान के मन्दिर से श्री देव धाम देव का हरवाडा जाएगी।

पदयात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। पदयात्री हाथों में ध्वज लेकर रवाना हुए। इस अवसर पर पदयात्री रंग बिरंगे कपड़े में सज धज कर डीजे की धुनों पर जमकर थिरकते नजर आए। इस अवसर पर भगवान देव नारायण का भव्य दरबार सजाया गया। श्रद्धालुओं ने धोक लगाकर परिवार को सुख समृद्धि की कामना की।

प्राप्त जानकारी के इस मौके पर जय राम भूमला, मूलचंद किलादार, ओम प्रकाश बागड़ी, विनोद किलादार, मालीराम बागड़ी, अशोक किलादार, श्रीराम मुकेश सुभाष महेश प्रकाश कजोड़ सुरज्ञान, मालीराम जांगिड़, परमानंद रग्गल मौजूद रहे।

नगर निगम ग्रेटर ने 14 हजार का कैरिंग चार्ज वसूला, 5 केन्टर सामान जब्त

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देशानुसार उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में गुरूवार को सतर्कता शाखा की टीम द्वारा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में पूर्व से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुये कैलाश टॉवर टोंक रोड, आई.बी.एस. हॉस्पिटल, डिग्गी रोड, खटीकों की डाल, नारायण हॉस्पिटल के सामने, 7 नं. चौराहा, एस.आई के द्वारा कैरिंग चार्ज, वार्ड नं. 117 जगतपुरा, यूनिवर्सिटी रोड बापू नगर, चौमू पुलिया, सीकर रोड, मुरलीपुरा 1 नं. रोड, निवारू रोड, 200 फिट बाईपास पुलिया के पास आदि स्थानों से अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध 14 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल कर 5 केन्टर सामान जब्त किया गया। उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार ने बताया कि नगर निगम ग्रेटर क्षेत्राधिकार में पूर्व से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुये कैलाश टॉवर टोंक रोड, आई.बी.एस. हॉस्पिटल, डिग्गी रोड, खटीकों की डाल, नारायण हॉस्पिटल के सामने, 7 नं. चौराहा, एस.आई के द्वारा कैरिंग चार्ज, वार्ड नं. 117 जगतपुरा, यूनिवर्सिटी रोड बापू नगर, चौमू पुलिया, सीकर रोड, मुरलीपुरा 1 नं. रोड, निवारू रोड , 200 फिट बाईपास पुलिया के पास आदि स्थानों से अस्थाई अतिक्रमण हटवाया गया। उपरोक्त कार्रवाई के दौरान 5 केन्टर सामान जब्त कर गोदाम में भिजवाया गया व अस्थाई अतिक्रमण करने वालों से मौके पर 14 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल किया गया तथा दौरे के दौरान कार्यवाही सतर्कता टीम द्वारा मौके पर समझाइश करते हुए मौखिक पाबंद करवाया कि भविष्य में अस्थाई अतिक्रमण समय से हटा ले अन्यथा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध भारी चालान या प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

शहीदों से प्रेरणा लेकर युवा देशसेवा के लिए आगे आएं- गृह राज्यमंत्री

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि देश की सीमाएं की रक्षा करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को आदर्श मानकर युवा देशसेवा के लिए आगे आएं। देश के लिए शहादत देने वाले शहीद हमेशा पूजे जाएंगे उनके बलिदान के कारण देश सुरक्षित है।

गृह राज्य मंत्री गुरुवार को भरतपुर जिले के बयाना के ग्राम श्यामपुरा में शहीद गूजरमल की प्रतिमा अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज भारत वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है। हमारे वीर सैनिकों ने भारत की सीमाओं पर अडिग रहकर दुश्मन देशों व आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जवान गूजरमल ने देश की सेवा में प्राण न्यौछावर कर सर्वोच्च बलिदान दिया है इसे कभी बुलाया नहीं जा सकताए युवाओं के लिए वे हमेशा मार्गदर्शन का कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारी सेना के जवानों ने पूरे विश्व को अपनी वीरता एवं कौशलता से बता दिया कि भारत अब 21वीं सदी का सशक्त व मजबूत इरादों का देश है। जवाहरसिंह बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओंए महिलाओंए किसानोंए मजदूरोंए उद्यमियों सहित सभी वर्गों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। देश की सीमाओं पर बलिदान देने वाले शहीद किसी एक वर्ग या क्षेत्र के नहीं होते हैं आने वाली पीढियां उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगी। सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से सरकार पूर्व सैनिकोंए शहीद परिवार की वीरांगनाओं एवं आश्रितों के लिए भी कल्याणकारी योजना चलाकर उनके साथ खडी हुई है। प्रतिमा अनावरण समारोह में शहीद वीरांगना एवं परिजनों का माल्यार्पण व शॉल ओढ़ा कर सम्मान किया गया। अतिथियों द्वारा शहीद गूजरमल की प्रतिमा का अनावरण कर पुष्पचक्र अर्पित किए। समारोह को उत्तरप्रदेश के सराधना विधायक अतुल प्रधान सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सम्बोधित किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष शिवानी दायमाए सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

राजीविका एवं वी. शक्ति ट्रस्ट दिल्ली के मध्य एक "गैर वित्तीय" समझौते पत्र पर हस्ताक्षर

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) एवं वी. शक्ति ट्रस्ट दिल्ली के मध्य गुरुवार को एक "गैर वित्तीय" समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते ज्ञापन को श्रीमती नेहा गिरी राज्य मिशन निदेशक राजीविका एवं श्रीमती प्रज्ञा यादव "फाउंडर एवं ट्रस्टी-वी शक्ति फाउंडेशन" द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। श्रीमती नेहा गिरी ने बताया कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों, शिल्पकारों और लघु व्यवसायियों को उनके उत्पादों और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उनकी आय को बढ़ाना, वित्तीय स्वतंत्रता की आपसी समझ तैयार करना। इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकते हुए लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता फैलाकर उन्हें सशक्त बनाने के समन्वित प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि राजीविका का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), ग्राम संगठनों (वीओ) और क्लस्टर स्तरीय संघों (सीएलएफ) में संगठित करके उनको विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रत्येक गरीब परिवार के लिए विविध रूप से आजीविकाओं को बढ़ावा देना है। गरीब एवं वंचित वर्ग की आय को बढ़ाने के लिए कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में लघु और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा दिया जाना है। राजीविका विभिन्न मार्ट एवं आउट लेट्स के माध्यम से निर्मित उत्पादों की बिक्री, सरकारी खरीद, ऑनलाइन बिक्री, निर्यात संवर्धन और सेवा क्षेत्र में अवसरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दे रहा है। वी शक्ति ट्रस्ट एक सार्वजनिक ट्रस्ट है, जो महिलाओं को कौशल एवं उनके संसाधनो को विकसित कर उनको प्रशिक्षण प्रदान करके उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाता है, साथ ही महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के साथ आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देता है। समावेशी अवसरों का सृजन करके सतत विकास को गति देता है जिससे महिलाएं अपने जीवन में बदलाव ला सकें, अपने समुदायों का उत्थान कर सकें एवं नवीन कार्यों के माध्यम से सृजन कर समतापूर्ण भविष्य में योगदान दे सकें। महिलाओं को उनकी आजीविका के लिए ऐसे अवसर प्रदान करना है जो संभावनाओं को साकार कर निरंतर एवं स्थाई आजीविका प्रदान करने में सहायक हो। राजीविका और वी शक्ति ट्रस्ट, सर्व प्रथम राजस्थान के अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हुए, ग्रामीण उद्यमिता, क्षमता निर्माण और लैंगिक समानता पर मजबूती से कार्य एवं सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। इस अनुबंध का समग्र उद्देश्य अलवर में अपनी गतिविधियों की शुरुआत करके धीरे-धीरे पूरे राजस्थान में विस्तार करके महिलाओं के जीवन में समग्र विकास और सार्थक बदलाव लाने, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के सरकारी प्रयासों को गति प्रदान करना है। यह समझौता पूर्ण रूप से गैर वित्तीय होगा। जिसमें स्वयं सहायता समूह सदस्यों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर विभिन्न क्षेत्रों में नए कौशल, पुनः कौशल विकास और कौशल उन्नयन कर छोटे व्यवसाय शुरू किये जा सकेंगे। वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत बचत और ऋण को समझना, डिजिटल भुगतान का उपयोग करना, डिजिटल कौशल यथा स्मार्टफोन का उपयोग, डिजिटल ऐप्स, इंटरनेट सुरक्षा, ऑनलाइन मार्केटिंग करना हैं।

'एक राष्ट्र—एक चुनाव' को लेकर राज्य स्तरीय छात्रसंघ प्रतिनिधि सम्मेलन

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने बताया कि राष्ट्रीय छात्रसंघ प्रतिनिधि सम्मेलन की तर्ज पर 30 अगस्त को राजस्थान में भी राज्य स्तरीय छात्रसंघ प्रतिनिधि सम्मेलन में एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया जाएगा। यह कार्यक्रम वैशाली नगर स्थित खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी कॉलेज में 11:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। भार्गव ने बताया कि राज्य स्तरीय छात्रसंघ प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य वक्ता राष्ट्रीय महामंत्री और एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी सुनील बंसल रहेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेशभर से 35 वर्ष से कम आयु के वर्तमान और पूर्व छात्रसंघ पदाधिकारी और छात्र प्रतिनिधि भाग लेंगे और एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करेंगे। सभी जिलों से करीबन 1250 छात्रसंघ प्रतिनिधि जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। भार्गव ने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव अवधारणा से देश की राजनीति में स्थिरता आएगी और विकास की गंगा बहेगी। चुनाव का भारी खर्च कम होगा, बचत को शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रा जैसे विकासात्मक कार्यों में खर्च किया जा सकेगा। लोकतंत्र की मजबूती के साथ एकजुटता आएगी। इससे देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में सुधार लाने के साथ एक सशक्त, स्थिर ओर समृद्ध भारत का निर्माण हो पाएगा।

आवश्यक नम्बर

रॉयल पत्रिका

बिजली फॉल्ट के लिए

टोल फ्री नंबर	18001806507
वॉट्सएप नंबर	9414037085
कस्टमर केयर	2203000
आईवीआरएस	1912

कचरा गाड़ी के लिए

ग्रेटर	2747400
सीवरेज लीकेज	2607500
हेरिटेज	2607500
टोल फ्री नंबर	14420

पुलिस की मदद के लिए

साइबर क्राइम	1930/2360094
कंट्रोल रूम	2388435/36/37/38
ट्रैफिक कंट्रोल रूम	2565630
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098
महिला हेल्पलाइन	1090
मुख्यमंत्री पोर्टल	181

पानी के लिए

जलदाय कार्यालय	2706624
फायर ब्रिगेड	2747400

मेडिकल इमरजेंसी के लिए

एंबुलेंस	102/108
एसएमएस इमरजेंसी	2518333
महिला चिकित्सालय	22610616
जनाना हॉस्पिटल	22378721
SDMH	22574189
SMS ब्लड बैंक	22518222
कल्याण ब्लड बैंक	22721771

घायल पशुओं के लिए

नगर निगम	2747400
बर्ड बाइक	9887345580
हेल्प इन सफरिंग	8107299711
जनमंच ट्रस्ट	7230055800
पशु चिकित्सालय	2747400

गीतांजली हॉस्पिटल के एक्टिव ट्रॉमा व इमरजेंसी स्टाफ को मिले गुड समेरिटन अवॉर्ड

उदयपुर (रॉयल पत्रिका)। गीतांजली हॉस्पिटल, राजस्थान परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग तथा आधार फाउंडेशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में हाल ही में स्व. नर्मदा देवी अग्रवाल ऑडिटोरियम में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुड समेरिटन अवॉर्ड्स उन जागरूक नागरिकों को प्रदान किए गए जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद कर मानवता का परिचय दिया। विभिन्न स्कूलों को उनकी प्रभावशाली प्रस्तुतियों के लिए भी सम्मानित किया गया। गीतांजली हॉस्पिटल की ओर से विशेष रूप से रेनू कोठारी, राहुल जैन, भगवती मेनारिया, नरेंद्र सिंह, भूपेश मेघवाल, पंकज सालवी, मनोज शर्मा, सुरेश पालीवाल, चिराग त्रिवेदी, भगवती लोहार, अतुल त्रिपाठी, भूषण गर्ग और मूकुल डांगी को उनके सहयोग और मानवता की भावना के लिए गुड समेरिटन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इन सभी को गीतांजली हॉस्पिटल के सीईओ ऋषि कपूर और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. हरप्रीत सिंह द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम सड़क सुरक्षा, ट्रॉमा केयर और मानवता की सेवा के महत्व को रेखांकित करते हुए शहरवासियों के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध हुआ।

रंधावा को दिया पाली आने का निमंत्रण

मोहम्मद यासीन

पाली(रॉयल पत्रिका)। अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव सांसद एवं प्रभारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सुखविंदर सिंह रंधावा के जोधपुर आगमन पर प्रदेश कांग्रेस सेवादल उपाध्यक्ष एवं जॉन प्रभारी मोहन हटेला, पाली जिला कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने मुलाकात कर पाली आने का निमंत्रण दिया। सेवादल जिलाध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने बताया की अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार पाली जिला कांग्रेस सेवादल का सोनाणा खेतलाजी देसूरी में संगठन सर्जन आवासीय प्रशिक्षण शिविर 13 सितम्बर को सुबह 8 बजे से शुरुआत होगी समापन 15 सितंबर को होगा जिसमें जिले के समस्त ब्लॉकों से 500 सेवादल कार्यकर्ता हिस्सा लेगे। चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सेवादल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट,नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजस्थान प्रदेश सेवादल अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, पूर्व राज्यमंत्री एवं पाली लोकसभा प्रत्याशी संगीता बेनीवाल, राज्य सभा सांसद नीरज डांगी,सेवादल प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जोधपुर, उदयपुर संभाग जॉन प्रभारी मोहन हटेला, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीज दर्द सहित विधायक,पूर्व विधायक, विधानसभा प्रत्याक्षी गण, प्रदेश एवं जिले के वरिष्ठ नेताओ को आंमत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में नेशनल एवं राज्य स्तर के प्रशिक्षक प्रशिक्षण देगे वहीं अलग अगल सत्र में प्रोफेसर शिविर को संबोधित करेंगे। पाली 27अगस्त अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव सांसद एवं प्रभारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सुखविंदर सिंह रंधावा के जोधपुर आगमन पर प्रदेश कांग्रेस सेवादल उपाध्यक्ष एवं जॉन प्रभारी मोहन हटेला, पाली जिला कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने मुलाकात कर पाली आने का निमंत्रण दिया। सेवादल जिलाध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने बताया की अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार पाली जिला कांग्रेस सेवादल का सोनाणा खेतलाजी देसूरी में संगठन सर्जन आवासीय प्रशिक्षण शिविर 13 सितम्बर को सुबह 8 बजे से शुरुआत होगी समापन 15 सितंबर को होगा जिसमें जिले के समस्त ब्लॉकों से 500 सेवादल कार्यकर्ता हिस्सा लेगे। चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सेवादल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट,नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजस्थान प्रदेश सेवादल अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, पूर्व राज्यमंत्री एवं पाली लोकसभा प्रत्याशी संगीता बेनीवाल, राज्य सभा सांसद नीरज डांगी,सेवादल प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जोधपुर, उदयपुर संभाग जॉन प्रभारी मोहन हटेला, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीज दर्द सहित विधायक,पूर्व विधायक, विधानसभा प्रत्याक्षी गण, प्रदेश एवं जिले के वरिष्ठ नेताओ को आंमत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में नेशनल एवं राज्य स्तर के प्रशिक्षक प्रशिक्षण देगे वहीं अलग अगल सत्र में प्रोफेसर शिविर को संबोधित करेंगे।

केडीए अध्यक्ष ने लॉन्च की शम्भूपुरा एकीकृत योजना

-पीएनबी कोटा की समस्त शाखाओं, केडीए से मिलेंगे आवेदन फार्म
-351 व्यावसायिक भूखंडों की बिक्री से 137 करोड़ रुपए आय की संभावना

शब्बीर हुसैन

कोटा (रॉयल पत्रिका)। संभागीय आयुक्त एवं कोटा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पीयूष समारिया ने गुरुवार को केडीए की शंभूपुरा एकीकृत योजना (व्यावसायिक गोदाम एवं व्यावसायिक होलसेल मार्केट योजना) लॉन्च की। इस योजना के तहत 351 व्यावसायिक भूखंड हैं। इसमें ब्लॉक 'ए' गोदाम के लिए 129 व्यावसायिक भूखंड जबकि ब्लॉक 'बी' में होलसेल मार्केट के लिए 222 व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध होंगे। योजना के तहत 351 व्यावसायिक भूखंडों के विक्रय से केडीए को करीब 137 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। भूखंडों का आवंटन केडीए द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। शंभूपुरा एकीकृत योजना कोटा-बूंदी एयरपोर्ट के समीप तथा हैगिंग ब्रिज से 4 किलोमीटर की दूरी, कोटा-चित्तौड़गढ़ रोड़ (नेशनल हाईवे-27) से आधा किलोमीटर की दूरी तथा कोटा-जयपुर रोड़ (नेशनल हाईवे-52) से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केडीए द्वारा योजना के समीप ट्रांसपोर्ट नगर, ट्रक रिपेयर वर्कशॉप, नगर योजना, चार्टर्ड अकाउंटेंट आवासीय योजना, पार्क एवं अन्य आवासीय योजनाओं का प्रावधान किया गया है। योजना को लॉन्च करते समय केडीए अध्यक्ष समारिया ने कहा कि यह योजना भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत कोटा-बूंदी एयरपोर्ट के समीप होने से काफी महत्वपूर्ण है और कोटा शहर के लिए प्राधिकरण की ओर से बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि स्थानीय व्यवसायी इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि इस योजना के आगे विस्तार की प्लानिंग भी प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। केडीए आयुक्त हरफूल यादव ने लॉन्चिंग के अवसर पर कहा कि यह योजना कोटा-चित्तौड़, कोटा-जयपुर रोड़ के करीब होने से काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए लॉजिस्टिक सोल्यूशन पहले से ही उपलब्ध है। व्यवसायी वर्ग में इस योजना को लेकर काफी उत्साह है।

केडीए अध्यक्ष पीयूष समारिया एवं केडीए आयुक्त हरफूल यादव ने इस अवसर पर योजना की बुकलेट भी रिलीज की। साथ ही, योजना के प्रचार-प्रसार के लिए गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लॉन्चिंग कार्यक्रम में प्रशिक्षु आईएएस आराधना चौहान, केडीए सचिव कुशल कोठारी, उप सचिव (भूमि अवाप्ति) मालविका त्यागी, निदेशक वित्त नीतू सिंह, निदेशक अभियांत्रिकी रविन्द्र माथुर, पीएनबी के मंडल प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

योजना के तहत आवेदन फार्म गुरुवार से मिलना प्रारंभ हो गए। आवेदन पंजाब नेशनल बैंक कोटा की समस्त शाखाओं, केडीए परिसर के काउंटर तथा अन्य जिलों में जिला मुख्यालय पर पीएनबी की नोडल शाखा से 500 रुपये शुल्क का भुगतान कर प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 होगी।

किशनपुरा के डॉ. जितेंद्र सिंह कीचड़ का सहायक आचार्य पद पर हुआ चयन

चौमूं (रॉयल पत्रिका)। ग्राम पंचायत किशनपुरा के खीचडो की ढाणी के निवासी जितेंद्र सिंह कीचड़ पुत्र झाबर सिंह जाट का क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में मिली नियुक्ति। डॉ. जितेंद्र खींचड बने सहायक आचार्य इन्होंने पूर्व में खीचड ने भारत सरकार के विभागों में सेवा दे चुके हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने उनके परिवार जनों को धन्यवाद और साधुवाद दिया। इस मौके पर महेश खीचड, श्याम खीचड सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

स्पिक मैके के द्वारा खुब जमी संगीत की स्वर लहरियां

-भारतीय संगीत व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है: अभिषेक सुराणा

मोहम्मद अली पठान

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर रामसरा बाईपास पर स्थित बैलमोंट हाई स्कूल में अन्तराष्ट्रिय ख्याती प्राप्त वाईलिन वादक उस्ताद जौहर अली ने स्पिक मैके के तहत अपनी विभिन्न राग रागिनीयों के द्वारा उपस्थित बच्चो एवम श्रोताओं को शास्त्रीय सुरो में जोड़कर झुमने पर मजबूर कर दिया। उन्होने राग अहिर भैरव आलाप रघुपति राघव राजा राम पश्चिम बंगाल राजस्थान के लोक धुनो पर वाईलिन बजाकर उपस्थित संगीत प्रेमियो की दाद बटोरी, उन्होने बच्चो से चर्चा करते हुऐ संगीता के 7 स्वरो एवम् पांच तारो वाले वाध्य यंत्रो की जानकारी दी एवम् जब सारे जहां से अच्छा हिन्दस्तान हमारा धुन को उन्होने अपनी वाईलिन पर बजाया तो उपस्थित बच्चो में राष्ट्रप्रेम की धारा दिखाई दी। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, स्पिक मैके चूरू के कॉडीनेटर कौशल दाधीच, बैलमोंट हाई स्कूल निदेशक अविनाश नेहरा, समाजसेवी अखिलेश चतुर्वेदी, वरिष्ठ संगीतज्ञ, डॉ श्यामसुन्दर शर्मा, दलीप नेहरा, शंकरलाल महर्षि, गुरूदास भारती, सगुफ्ता खांन, अनिल झिरमिरियां, आन्नद महर्षि, रवि दाधीच और बैलमोंट हाई स्कूल प्रधानाचार्या नीतू नेहरा मचस्थ रहे। इस अवसर पर संस्था निदेशक अविनाश नेहरा ने सभी का स्वागत करते हुऐ कहा कि संस्था में शिक्षा के साथ साथ सहशैक्षिक गतिविधियां भी चलाई जाती है। जिसमें संगीत की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। उन्होने अन्तराष्ट्रिय कलाकार उस्ताद जौहर अली के इस प्रदर्शन के लिए उनका आभार जताया। स्पिक मैके के चूरू कॉर्डिनेटर कौशल दाधीच ने आभार जताते हुऐ कहा कि चूरू में स्पिक मैके के द्वारा अनेक अन्तराष्ट्रिय कलाकारो के द्वारा बच्चो के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये है आने वाले समय में यह कार्यक्रम यू ही चलते रहेगे और अनेक अन्तराष्ट्रिय कलाकार चूरू आकर अपनी कला का प्रदर्शन करेगे एवम् बच्चो को भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी देगे। कार्यक्रम का संचालन मुकुल भाटी ने किया। कार्यक्रम में बैलमोंट हाई स्कूल के स्टॉफ सदस्य, छात्र छात्राऐं उपस्थित रही और उन्होने भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में अपनी जिज्ञासा का समाधान किया।

नोपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वार व वह मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ

चौमूं (रॉयल पत्रिका)। ग्राम पंचायत हस्तेडां कस्बे के ग्राम नोपुरा बमपुरी आश्रम के पास ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्थित विद्यालय में का ए वर्षो से मुख्य द्वार झर-झर अवस्था में होने के कारण इसको लेकर स्थानीय 108 बम महाराज मुख्य द्वार एवं मूर्ति यो के द्वारा विद्यालय भी एक मंदिर समझकर निर्माण करवाया गया। इसको लेकर ग्राम नोपुरा बमपुरी आश्रम बम महाराज को विद्यालय का निर्माण करवाने ग्रामीण तथा विद्यालय प्रशासन धन्यवाद दिया। इस विद्यालय मुख्य द्वार वी मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजा - अर्चना करवा कर स्थानीय अध्यापक यजमान मास्टर प्रकाशम यादव के द्वारा मुख्य द्वार एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना करवाई गई। इस मौके पर बम आश्रम के 1008 बम महाराज ने बताया कि मंदिर मेरा आश्रम है ऐसा ही विद्यालय भी एक मंदिर के समान माना गया है इसलिए मैंने मेरे आश्रम की ओर से यह निर्माण करवाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक बाबूलाल वशिष्ठ, शिक्षक प्रकाश चंद्र यादव, रामलाल शर्मा , धीरज दीक्षित, जगदीश प्रसाद बुनकर, किशनपुरा से मानाराम रोज, कांता देवी रैगर , पूनम खंडेलवाल, अमित सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

कांग्रेस सेवादल की ज़िला स्तरीय बैठक संपन्न, सितंबर माह में लगेगा 3 दिवसीय शिविर

शब्बीर हुसैन

बारां(रॉयल पत्रिका)। ज़िला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस सेवादल जिला स्तरीय बैठक सेवादल ज़िला अध्यक्ष शिवशंकर यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कांग्रेस सेवादल ज़िला मीडिया प्रभारी ज़ाकिर खान ने बताया कि बैठक में संभागीय प्रभारी मास्टर श्याम सुंदर शर्मा और सेवादल प्रदेश सचिव अशरफ देशवाली अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रबंधन करते हुए सेवादल जिला प्रशिक्षक नासिर मिर्ज़ा ने सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत भाषण में जानकारी देते हुए अध्यक्ष शिवशंकर यादव ने जिले में सेवादल द्वारा चलाई जा रही संघटन की गतिविधियों की जानकारी दी तथा आगामी सितंबर माह में होने वाले तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताया। बैठक में संभागीय प्रभारी मास्टर श्यामसुंदर शर्मा ने बताया कि बारां जिले में सेवादल की जिला स्तरीय सहयोगी प्रशिक्षण शिविर सितंबर माह में 29, 30 व 1 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएगा। इस शिविर में सेवादल के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित कांग्रेस संघटन के कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस अवसर पर संभाग प्रभारी मास्टर श्याम शर्मा, सेवादल जिला अध्यक्ष शिवशंकर यादव, प्रदेश सचिव अशरफ देशवाली, जिला प्रशिक्षक नासिर मिर्ज़ा, महिला जिलाध्यक्ष दुर्गेश धनवंतरी, सेवादल यंग ब्रिगेड जिला अध्यक्ष शिवराज मीणा, किशनगंज ब्लॉक अध्यक्ष लेखराज शर्मा, नगर अध्यक्ष रोहित गुर्जर, मांगरोल नगर अध्यक्ष आसिफ अली, उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा भूलहेड़ी, मनोज ओझा, आशाराम बैरवा, मारूफ लाला, युवा नेता विजय बैरवा, जिला परिषद् सदस्य गजेंद्र सुमन, प्रिया बैरवा, सोनू वाल्मीकि, मुकेश यादव,मोहन, राहुल यादव आदि मौजूद थे।

आत्मा परियोजना के तहत कृषक-वैज्ञानिक संवाद

हनुमानगढ़ (रॉयल पत्रिका)। आत्मा परियोजना के अंतर्गत बुधवार को हनुमानगढ़ आत्मा परियोजना कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक दिवसीय कृषक-वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के लगभग 60 प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारम्भ उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा सुभाष चन्द्र डूडी ने किसानों का स्वागत करते हुए किया। उन्होंने आत्मा परियोजना की उपयोगिता पर विस्तृत जानकारी दी और कहा कि ऐसे संवाद किसानों को नई तकनीक एवं वैज्ञानिक जानकारी से जोड़ने का सशक्त माध्यम हैं। इस अवसर पर कृषि अनुसंधान केन्द्र श्रीगंगानगर के क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक डॉ. ए.के. शर्मा ने किसानों से सीधे संवाद कर कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और बदलते तकनीकी परिदृश्यों से किसानों को अवगत कराया। केवीके संगरिया के विषय विशेषज्ञ (शस्य) डॉ. चन्द्रशेखर शर्मा ने फसल अवशेष प्रबंधन एवं खरीफ व रबी फसलों में उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर विस्तृत जानकारी दी। वहीं विषय विशेषज्ञ (पौध संरक्षण) डॉ. उमेश कुमार ने खरीफ फसलों विशेषकर बीटी कपास में कीट एवं व्याधि प्रबंधन की प्रभावी तकनीकों पर प्रकाश डाला। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी अभिषेक गोदारा ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की महत्ता बताते हुए पौधों में पोषक तत्वों के संतुलित प्रबंधन के तरीके साझा किए। उद्यान उपनिदेशक डॉ. रमेश चन्द्र बराला एवं सहायक निदेशक साहबराम गोदारा ने किसानों से संवाद कर शस्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों को अपनाने पर बल दिया और कहा कि फसल विविधीकरण से किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। इसी क्रम में कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर के वैज्ञानिक डॉ. हरजिन्द्र सिंह ने बीटी कपास में रसचूसक कीट एवं गुलाबी सुंडी नियंत्रण पर प्रभावी जानकारी दी। कृषि अनुसंधान अधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने खरीफ फसलों में की जाने वाली समसामयिक कृषि क्रियाओं की जानकारी प्रदान की। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजवीर सिंह ने किसानों को पशुपालन का वैज्ञानिक प्रबंधन तथा पशुपालन विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। आत्मा परियोजना के उप परियोजना निदेशक करणजीत सिंह एवं वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक रामलाल गोदारा ने किसानों को प्राकृतिक खेती एवं जलवायु अनुकूल खेती के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए टिकाऊ खेती की दिशा में प्रयास करना समय की मांग है।

कालाडेरा पुलिस व डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई

चौमूं (रॉयल पत्रिका)। पुलिस ने ऑपरेशन नॉकआउट अभियान के तहत की कार्रवाई आरोपी संजय सांसी निवासी कालाडेरा को किया गिरफ्तार । पुलिस ने आरोपी के पास में अवैध मादक पदार्थ 305 ग्राम गांजा किया बरामद पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान बेचने वाले कालाडेरा SHO बाबूलाल मीणा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। गोविंदगढ़ सीओ राजेश जांगिड़ के सुपरविजन में हुई कार्रवाई।

कॉमन सीनियरिटी के लिए दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को प्राध्यापक स्कूल शिक्षा कॉमन सीनियरिटी संघर्ष समिति की चुरू उपशाखा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उपप्राचार्य पदोन्नति वर्ष 2023-24 में 2024-25 में व्याख्याता में कॉमन सीनियरिटी बनाकर पदोन्नति करने का आग्रह किया। अभी यह मामला माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैच में चल रहा है। राज्य सरकार से यह मांग की गई है कि न्यायालय की सुनवाई पूरी होने के बाद ही यह पदोन्नति की जाए क्योंकि उपप्राचार्य पद को वर्तमान में डाइंग कैडर बना दिया है इसलिए इस पदोन्नति के रुकने पर विद्यालय स्तर पर कोई नुकसान नहीं होगा। इस दौरान व्याख्याता मनोज श्योराण,आरिफ खान, आसिफ खान, मोहन कलकल, भंवरलाल बुडानिया, दलित मीणा सहित कई व्याख्याता उपस्थित रहे।

तेजाजी मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा

मोहम्मद अली पठान

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय के नजदीक बाड़की गांव के तेजाजी मंदिर में अतिथियों ने तेजाजी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। मंदिर में पण्डितजनों ने मंत्रोच्चारण से ग्रामीणों को पूजा अर्चना करवाई। इस मौके पर ग्रामीणों ने हवन में आहूतियां देकर देश व राज्य में खुशहाली की मंगल कामना की। पूर्व सभापति गोविन्द महनसरिया ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जिससे मनुष्य के कष्टों का निवारण होता है। मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान उसकी सुनकर उसे सफलता की ओर लेकर जाए। इस अवसर पर ग्रामीणों ने मंदिर में सहयोग करने वालो व अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान गांव में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा की। कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर में पंहुची। इस अवसर पर मूर्ति दानदाता सोहनलाल रणवा, अनिल कासनिया, राजेन्द्र कस्वां, हेमन्त सिहाग, रामनिवास सहारण, किसनाराम बाबल, लक्ष्मणराम मीणा, काशीराम नाई, प्रहलाद शर्मा, पूर्णाराम मेघवाल, मनीराम कुलड़िया, दीपचन्द गोदारा, बजरंगलाल नेहरा, सुरेन्द्र डूडी, राजेश दड़िया आदि सहित ग्रामीण मौजूद रहे। संचालन सुरेन्द्र कुलड़िया ने किया।

जैन श्वेतांबर समाज ने मनाया क्षमावाणी पर्व किया सम्मान

शब्बीर हुसैन

बारां (रॉयल पत्रिका) । श्री जैन श्वेताम्बर समाज मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र रंगावत, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि जैन श्वेताम्बर संघ के श्री चंद्रप्रभू मंदिर में चल रहे पर्यूषण पर्व धार्मिक कार्यक्रमों के साथ सम्पन्न हो जाने के उपरान्त आज चन्द्रप्रभू मंदिर में सकल श्रीसंघ द्वारा क्षमावाणी पर्व मनाया गया। इस दौरान सभी समाज बंधुओं ने एक-दूसरे से क्षमा मांगी तथा क्षमा दी। सभी ने संवत्सरी प्रतिक्रमण करते हुए एक-दूसरे के गले मिलकर इस पर्व को मनाया।

चन्द्रप्रभू महिला मण्डल अध्यक्ष एवं जिला प्रमुख श्रीमती उर्मिला जैन भाया, रेखा बोरडिया, खुशबू मारू, मोना, रेखा बोरडिया ने बताया कि आज श्री जैन श्वेताम्बर समाज मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र रंगावत, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, कोषाध्यक्ष गौत्तम बोरडिया द्वारा पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व की आराधना करवाने हेतु उपासना मंदिर अरिहंत बंगलो-मुम्बई (महाराष्ट्र) से पधारे साधर्मिक क्रिश सतीश भाई रांका, कलश अश्विन भाई तथा श्री चन्द्रप्रभू मंदिर के राजेश जी पुजारी का सकल श्रीसंघ द्वारा सम्मान किया गया। 9 दिन के तप करने पर प्रीति रंगावत को शुभकामनाएं दी गई।

अजमेर बनेगा खेलों का नया हब, खिलाड़ियों को मिलेगी नई पहचान- देवनानी

विधानसभा अध्यक्ष ने किया एथेलेटिक्स खेल अकादमी का लोकार्पण

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के एथेलेटिक्स खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बजट घोषणा के अनुरूप अजमेर में एथलेटिक्स अकादमी का लोकार्पण किया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा संचालित एथलेटिक्स खेल अकादमी का लोकार्पण बुधवार को पटेल स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। लोकार्पण अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि एथेलेटिक्स खेल अकादमी के भवन का लोकार्पण युवाओं के सपनों की उड़ान है। यह दिन अजमेर के खेल इतिहास का स्वर्णिम दिवस होगा। यह अकादमी राजस्थान की शान और भारत का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के लिए एक नई पहचान बनेगी। इस अकादमी में 30 खिलाड़ियों के लिए भोजन, शिक्षा एवं खेल प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वर्ष 2024 के बजट में अजमेर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एथलेटिक्स खेल अकादमी की घोषणा की थी। देवनानी ने कहा कि मैंने कॉलेज शिक्षा के समय से ही यह निश्चय था कि खेलों के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। खिलाड़ियों को पहचान मिले और उन्हें परंपरागत खेलों को भी अपनाना चाहिए। कबड्डी एक ऐसा ही खेल है, जिसमें खर्च कम होता है और हमारे जिले में इसके उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं। खेल केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि परिश्रम, अनुशासन और प्रतिभा का प्रतीक है। इसमें जात-पात से ऊपर उठकर हर खिलाड़ी की प्रतिभा को सम्मान मिलता है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्णिम भाला फेंक कर देश को गौरवान्वित किया और पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया। खेलों में कोई हारता नहीं है यह हमें पुनः लड़ने की प्रेरणा देता है। खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों से सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। मेरी आकांक्षा है कि आने वाले समय में अजमेर का खिलाड़ी ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े आयोजनों में भाग लेकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करे। देवनानी ने कहा कि अकादमी के लोकार्पण से अजमेर खेलों का हब बनेगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी स्थानीय खेलों से परिचित होंगे। उन्होंने कहा कि बड़े सपने और कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी हैं। यह अकादमी युवाओं के सपनों को दिशा देगी और वे देश का तिरंगा अंतरराष्ट्रीय मैदानों में लहराएंगे। उन्होंने जर्मनी में आयोजित वल्र्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीतने पर खिलाड़ी महिमा चौधरी को शुभकामनाएं भी दीं।

शांति समिति बैठक में डोल मेला आयोजन पर विस्तृत चर्चा

-अतिक्रमण, साफ सफाई व सुरक्षा प्रमुख मुद्दे रहे
-बारां में 3 सितंबर से शुरू होगा प्रसिद्ध डोल मेला

शब्बीर हुसैन

बारां(रॉयल पत्रिका)। जिले में आगामी दिनों में त्योहारों व डोल मेला आयोजन के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जन सुविधा केंद्र में जिला शांति समिति एवं डोल मेला की तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर तोमर ने कहा कि त्योहारों एवं डोल मेले के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी विभाग आपसी समन्वय से बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि वे आपसी भाईचारे और सद्भाव की परंपरा को बनाए रखें, प्रशासन को सहयोग दें और अनुशासन पूर्वक त्योहारों का आनंद लें। विधायक राधेश्याम बैरवा ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं एवं आमजन की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए तथा किसी को असुविधा न हो, इसके लिए अधिकारी समय रहते पुख्ता प्रबंध करें। एसपी अभिषेक अंदासु ने बताया कि मेले व त्योहारों के दौरान पुलिस की विशेष तैनाती की जाएगी तथा सुरक्षा चाक-चौबंद रखने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। बैठक में प्रधान मोरपाल सुमन, एडीएम दिवांशु शर्मा, एएसपी राजेश चौधरी, एसई राजवीर सिंह चौधरी, एसडीएम विश्वजीत सिंह सहित अधिकारी, समाजसेवी, शांति समिति के सदस्य एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। बैठक के दौरान नगर परिषद द्वारा 9 अखाड़ों को 24-24 हजार रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई, ताकि डोल मेले में पारंपरिक आयोजन बेहतर व सुचारू रूप से किया जा सके।

शांति समिति सदस्यों के सुझाव

शांति समिति सदस्य राकेश जैन ने कहा कि डीजे की तेज आवाज से हार्ट मरीजों और बुजुर्गों को खतरा रहता है तथा दुकानों के शीशे व जर्जर भवनों के प्लास्टर तक क्षतिग्रस्त होते हैं, इसलिए ध्वनि सीमा तय की जानी चाहिए। व्यापार महासंघ अध्यक्ष योगेश कुमरा ने सुझाव दिया कि दीपावली तक अतिक्रमण हटाओ अभियान को सीमित रखा जाए, जिससे त्योहारी सीजन में व्यापार पर प्रतिकूल असर न पड़े। जयेश गालव ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का मुद्दा उठाया। इसके अलावा महावीर नामा (व्यायामशाला), अखलाक अंसारी, माजिद सलीम, जाकिर मंसूरी, हरगोविन्द जैन, खेमसिंह डागर सहित कई प्रबुद्धजन बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में सभी ने शांति, सद्भाव एवं बेहतर व्यवस्थाओं के साथ आगामी त्योहारों और डोल मेले को सफल बनाने का संकल्प लिया। शांति समिति सदस्यों ने त्योहारों के दौरान अतिक्रमण हटाने, अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, साफ-सफाई व्यवस्था, वाहन पार्किंग की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक, जर्जर भवनों से सुरक्षा, बिजली के तारों से बचाव तथा अराजक तत्वों पर निगरानी जैसे मुद्दे उठाए।

गूगल मैप से बंद मार्ग पर चले जाने से वाहन पानी के तेज बहाव में बहा

-वाहन में सवार थे 9 व्यक्ति, 5 व्यक्तियों को सुरक्षित बचाया गया
-4 व्यक्तियों की जान गई, 3 के शव मिले, एक की तलाश जारी

चित्तौड़गढ़ (रॉयल पत्रिका)। राशमी कस्बे के पास देर रात भीलवाड़ा से आ रहे वाहन चालक ने गूगल मैप से रास्ता ढूंढते हुए बंद मार्ग पर चले जाने से वाहन पानी के तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलते ही स्थानीय स्तर पर बचाव कार्य शुरू किया गया तथा प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया गया। इस दौरान उपरेड़ा निवासी अब्दुल जब्बार पुत्र शरीफ ने अपने जीवन की परवाह किए बिना नदी के बहाव के विपरीत जाकर 5 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला। दुर्भाग्यवश 4 व्यक्तियों को बचाया नहीं जा सका, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। अब तक 3 व्यक्तियों के शव बरामद कर लिए गए हैं जबकि एक की तलाश जारी है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अर्जुनलाल जीनगर, जिला कलक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी सहित संपूर्ण प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद रहकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है।

गोगामेड़ी पशु मेले में 30 अगस्त से 1 सितंबर तक होगी पशु प्रतियोगिताएं

-पशुपालकों को 1.68 लाख रुपए नकद पुरस्कार

हनुमानगढ़ (रॉयल पत्रिका)। गोगामेड़ी पशु मेला-2025 का आगाज 9 अगस्त से हो चुका है, जो 7 सितम्बर तक गोगामेड़ी में चलेगा। इस बार मेले में पशुपालन विभाग और देवस्थान विभाग के संयुक्त प्रयासों से 30 अगस्त से 1 सितम्बर, 2025 तक विभिन्न पशु प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्रतियोगिताओं में गाय, भैंस, घोड़ी, ऊँट और ऊँटनी शामिल रहेंगे। विजेताओं को कुल 1,68,550 रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिताओं की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पंजीकरण से होगी। 31 अगस्त को गाय (साहीवाल) और भैंस (मुर्रा) प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जबकि 1 सितम्बर को मारवाड़ी नस्ल की घोड़ी, ऊँट और ऊँटनी की प्रतियोगिता होगी। प्रत्येक वर्ग में प्रथम पुरस्कार 15,100 रुपये, द्वितीय 7,100 रुपये, तृतीय 4,000 रुपये तथा पाँच सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. आनंद ने बताया कि पशुपालकों के लिए रजिस्ट्रेशन निःशुल्क रहेगा। मेले में चिकित्सा, बिजली और पानी की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध होगी। पारितोषिक वितरण समारोह 1 सितम्बर को शाम 4 बजे आयोजित होगा। सभी पशुपालकों से अपील है कि वे अपने उन्नत नस्ल के पशुओं को लेकर मेले में पहुंचे और प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लें।

जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित

लंबित कार्यों को पूरा कर जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए-जिला कलक्टर

धौलपुर (रॉयल पत्रिका)। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने उन योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा, जिनका कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुका है और जलापूर्ति चालू करना शेष है। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसी योजनाओं को शीघ्र ही ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को हस्तांतरित किया जाए, ताकि ग्रामीण स्तर पर जलापूर्ति की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन के अधीन रहे और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान तत्परता से किया जा सके। बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने निर्देश धीमी गति से चल रहा है वहां संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी किया जाए और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है, उनका धरातल पर भी प्रभावी रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर में नियमित जलापूर्ति करने के निर्देश दिए। जल स्त्रोतों की गुणवत्ता परीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता जताई। उन्होंने निर्देश दिए गए कि स्वीकृत योजनाओं की कार्य गति को तेज किया जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ए एन सोमनाथ ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन की प्राथमिकताओं को गंभीरता से लेने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जल पाइप लाइन बिछाने के बाद रोड रिपेयर की थर्ड पार्टी से जांच कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में विधायक राजाखेड़ा रोहित बोहरा, विधायक बसेड़ी संजय जाटव, अधीक्षण अभियंता पीएचईडी राजकिरण यादव, अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल राजेश कुमार वर्मा, पीएचईडी के खंड धौलपुर-बाड़ी के अधिशाषी अभियंता, सभी उपखंडों के सहायक अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोकथाम एवं जनजागरूकता अभियान

चित्तौड़गढ़ (रॉयल पत्रिका)। जिला कलक्टर आलोक रंजन के निर्देशानुसार नगर परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा बुधवार को चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर, विजय स्तंभ एवं फतह प्रकाश महल के आस-पास स्थित व्यवसायिक एवं आवासीय क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध जनजागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान आमजन एवं पर्यटकों को समझाइश दी गई कि सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक बैग, बोतलें एवं पैकेजिंग सामग्री से न केवल कचरा और प्रदूषण बढ़ता है बल्कि इसमें पाए जाने वाले रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। फेंके गए प्लास्टिक से सड़कों पर गंदगी फैलती है और आसपास का वातावरण बदसूरत होता है। इसके विकल्प के रूप में पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को अपनाने हेतु कपड़े के थैलों का वितरण किया गया। साथ ही दुकानदारों एवं रेहड़ी वालों को गीले एवं सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन का उपयोग करने, कचरा सड़क पर नहीं फैलाने और उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डालने के लिए प्रेरित किया गया। नगर परिषद टीम द्वारा कार्रवाई के दौरान 90 किलो पॉलिथीन जप्त कर ₹6800 का जुर्माना भी वसूला गया। इस अवसर पर आमजन से दुर्ग क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त रखने की अपील की गई।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 1252 यात्रियों का चयन

-134 यात्री हवाई जहाज से एवं 1118 यात्री रेल से करेंगे यात्रा

चित्तौड़गढ़ (रॉयल पत्रिका)। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 के तहत देवस्थान विभाग एवं प्रभारी मंत्री के निर्देशानुसार विभाग की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को रेल एवं हवाई मार्ग से धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने के लिए बुधवार को जिला कलक्टर आलोक रंजन की उपस्थिति में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DOIT) में लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न की गई। जिला कलक्टर आलोक रंजन ने बताया कि कुल 3795 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से वैधानिक प्रक्रिया के तहत कुल 1252 यात्रियों का चयन किया गया है, जिनमें से 134 यात्री हवाई जहाज से तथा 1118 यात्री रेल द्वारा तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। जिला कलक्टर ने चयनित यात्रियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन में यादगार अवसर है, जिससे उन्हें धार्मिक स्थलों के दर्शन का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि चयनित यात्रियों के प्रतीक्षा सूची एवं अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची भी तैयार की गई है। सभी चयनित यात्रियों को विभाग की ओर से SMS के माध्यम से सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक, अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू.अ.) रामचंद्र खटीक, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश पुरोहित, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ताराचंद गुप्ता, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपनिदेशक प्रवीण जैन, पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक विवेक जोशी, देवस्थान विभाग के सुनील मीना, पुलिस विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2025 के लिए ऑनलाईन निकाली लॉटरी

-जिले से 121 वरिष्ठ नागरिक करेंगे हवाई यात्रा तथा 1006 को रेल से तीर्थ यात्रा का मिलेगा अवसर

डूंगरपुर (रॉयल पत्रिका)। राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंशानुरूप वरिष्ठ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनकी आस्थाए सस्कृति एवं धार्मिक परंपराओं जोडे रखने के लिए सतत् प्रयासरत है। देवस्थान विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2025 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले की लॉटरी प्रक्रिया बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर के सूचना विज्ञान केन्द्र में जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में एवं लॉटरी समिति की उपस्थिति में संपन्न की गई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनान्तर्गत जिले में हवाई यात्रा के लिए कुल 2930 प्राप्त आवेदन में से 121 तथा रेल यात्रा के लिए कुल 3865 प्राप्त आवेदन में से 1006 यात्रियों का चयन कर कुल 1127 यात्रियों का चयन किया गया। सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग दीपिका मेघवाल ने बताया कि रेल द्वारा यात्राओं में हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या, द्वारिकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरुपति, गंगासागर, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, वैष्णोदेवी, महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर सहित अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल सम्मिलित हैं। वहीं हवाई यात्रा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर दिनेश चंद्र धाकड़ मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, एडिशनल एसपी राजीव परिहार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अलंकार गुप्ता, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग दीपिका मेघवाल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग संयुक्त निदेशक मुकेशए वर्मा उपनिदेशक समीर मीणा उपस्थित रहें।

सीताफल उत्कृष्टता केंद्र पर दो दिवसीय कृषक–वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित

चित्तौड़गढ़ (रॉयल पत्रिका)। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़ पर दो दिवसीय कृषक-वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग 30 कृषकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कृषकों को कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन से संबंधित नवीनतम जानकारियाँ प्रदान की गईं, साथ ही जल संरक्षण, जल प्रबंधन एवं विभागीय योजनाओं के बारे में भी मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप निदेशक कृषि एवं परियोजना निदेशक आत्मा डॉ. प्रेमचंद वर्मा ने किया। उन्होंने आत्मा योजना की जानकारी देते हुए कृषकों से कृषक पुरस्कार हेतु आवेदन करने की अपील की। संयुक्त निदेशक कृषि दिनेश कुमार जागा ने प्राकृतिक खेती एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इसी क्रम में उप निदेशक उद्यान डॉ. शंकरलाल जाट ने उद्यान विभाग की योजनाओं के साथ-साथ पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक आवेदन करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने जल बचत योजनाओं जैसे – डब्ल्यूएचएस, संरक्षित खेती एवं माइक्रो इरिगेशन के लाभ लेने की अपील की। कार्यक्रम में उप निदेशक आईपीएम डॉ. ओमप्रकाश शर्मा ने ट्राईकोडर्मा के उपयोग पर बल दिया। वहीं पशुपालन विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मौसमी बीमारियों के लक्षण एवं उनके उपचार की जानकारी दी। इस अवसर पर आत्मा परियोजना के उप परियोजना निदेशक डॉ. हरीश कुमार टांक, कृषि अधिकारी नवनीता शेखावत, दिनेश झंवर सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

विजन डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान-2047

-राज्य को आर्थिक समृद्धि, सतत् विकास एवं समावेशी प्रगति की दिशा में सशक्त कदम

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, सतत् विकास एवं समावेशी प्रगति के विजन डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान-2047 को मंजूरी दी गई है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप राज्य सरकार के 'विकसित राजस्थान-2047' विजन डॉक्यूमेंट का मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया। राज्य को आर्थिक समृद्धि, सतत् विकास एवं समावेशी प्रगति की दिशा में सशक्त, आत्मनिर्भर एवं विकसित बनाने का रोडमैप है। विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप संबंधित विभाग विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा वित्तीय आवश्यकताओं का वर्षवार आकलन कर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इसकी क्रियान्विति करेंगे। इस विजन डॉक्यूमेंट में राजस्थान को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जनकल्याण एवं सामाजिक सशक्तीकरण, तीव्र विकास एवं रोजगार सृजन, भविष्य उन्मुख राजस्थान के लिए भौतिक अवसंरचना और सतत विकास तथा सहायक आधार नीति, वित्त एवं शासन थीम्स को शामिल किया गया है। इस दस्तावेज में शत-प्रतिशत साक्षरता, छात्र-केंद्रित और कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली, युवाओं और महिलाओं का सशक्तीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता,हरित ऊर्जा को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विभिन्न विकास कार्यों का किया शुभारंभ

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को वार्ड 62 और 63 में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। देवनानी ने वार्ड 62 स्थित इंदिरा कॉलोनी में गलियों में सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की। उन्होंने सड़क निर्माण को क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सुविधा बताया। इसके पश्चात उन्होंने वार्ड 63 में प्रताप नगर पुलिया से श्मशान तक नाले के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर के समग्र विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को त्वरित गति से विकसित किया जा रहा है। सड़क एवं नाला निर्माण से नागरिकों को आवागमन, स्वच्छता एवं जल निकासी की बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने आमजन से शहर को स्वच्छ रखने, विकास कार्यों में सहयोग और निर्माण कार्य की निगरानी करने का आह्वान भी किया। देवनानी ने कहा कि बजट घोषणा के तहत बन रहे आईटी पार्क में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। काजीपुरा क्षेत्र में रमणीय लेपर्ड सफारी भी विकसित की जाएगी। अजमेर को श्रेष्ठ बनाने के लिए शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन सुविधाओं का व्यापक विकास किया जा रहा है। इस कार्यकाल में प्रारंभ किए गए अधिकांश कार्य अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि स्पीकर हेल्प डेस्क जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में संचालित हो रही है। इससे पाँच हजार से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक रुपये में भोजन की योजना भी चलाई जा रही है। यह सब कार्य आमजन के सहयोग और सहभागिता से संभव हो पाया है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा

डीएमआईएस पोर्टल पर करना होगा आवेदन- खोरवाल

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों को निर्धारित मानकों के अनुसार राहत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अतिरिक्त जिला कलक्टर वंदना खोरवाल ने बताया कि आपदा के दौरान सार्वजनिक परिसम्पत्तियों, घरों, फसलों, पशुधन अथवा मानव मृत्यु की स्थिति में पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के प्रावधान हैं। खोरवाल ने जानकारी दी कि प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों तथा जन हानि, घायल तथा पशु हानि तथा कच्चे एवं पक्के मकान की क्षति अथवा फराल खराबा इत्यादि पर प्रभावितों को नियमानुसार तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मानव मृत्यु पर प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए, मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर कपड़ों के लिए प्रति परिवार 2500 रुपए, बर्तन और घरेलू सामान पर प्रति परिवार, 2500 रुपए, समतल क्षेत्र में बना कच्चा अथवा पक्का घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने पर प्रति घर एक लाख 20 हजार रुपए, पहाड़ी क्षेत्र में बना कच्चा तथा पक्का घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने पर प्रति घर एक लाख 30 हजार रूपए, पक्का घर कम से कम 15 प्रतिशत आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर प्रति घर 6 हजार 500 रुपए, कच्चा घर आंशिक कम से कम 15 प्रतिशत क्षतिग्रस्त होने पर प्रति घर 4 हजार रुपए, झोपड़ियों की क्षति पर प्रति झोपड़ी 8 हजार रुपए।

रीजनल सिनेमा में अलग तरह के कंटेंट पर फिल्म बनाने की पूरी आजादी होती है

अजय देवगन ने जब नई स्टारकास्ट के साथ गुजराती फिल्म वश का हिंदी रीमेक शैतान बनाया, तो फिल्म की मुख्य अदाकारा जानकी बोडीवाला को रिप्लेस नहीं कर सके। वश में आर्या और शैतान में जाह्नवी के रोल में जानकी ने गुजराती और हिंदी दोनों ही भाषाओं के दर्शकों का दिल जीता। अब वह वश लेवल 2 में नजर आने वाली हैं। यह 2023 में आई वश का ही सीक्वल है। फिल्म 27 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड और गुजराती फिल्मों में काम करने के अपने अनुभव, दोनों इंडस्ट्री के बीच अंतर पर खुलकर बात की। जानकी ने माना कि रीजनल सिनेमा में अलग तरह के कंटेंट पर फिल्म बनाने की पूरी आजादी होती है, जबकि बॉलीवुड में बहुत हद तक यह मुमकिन नहीं हो पाता।

आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो अचानक फिल्मों में आना कैसे हुआ?

मैं मतलब डॉक्टर बैग्राउंड से होने वाली थी। मगर मैंने वह पढ़ाई कम्पलीट नहीं की। इसी दौरान मुझे मेरे डायरेक्टर कृष्णदेव यागि्नक (डेब्यू फिल्म के निर्देशक) मिल गए जिन्होंने मुझे गुजरात में पहचान दिलाई। यह उनका ही फैसला था कि वह मुझे अपनी पहली फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। और उन्होंने ही फिल्म वश भी बनाई जिसके लिए ना सिर्फ मुझे पूरे देश में पहचान मिली, बल्कि राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला।

अभी आप वश 2 में काम कर रही हैं जो हिंदी में रिलीज हो रही है। बाद में हो सकता है कि आप शैतान के सीक्वल में भी हों, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा उस समय, क्योंकि लोग वश 2 देख चुके होंगे?

शैतान का अंत गुजराती फिल्म वश से अलग था। तो शायद वह अपना एक अलग यूनिवर्स क्रिएट करेंगे। हालांकि उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन हां, मुझे दोनों फिल्मों में काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। इतने बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला।

आप गुजरात फिल्म इंडस्ट्री के विकास को किस तरह से देखती हैं?

रीजनल सिनेमा में अच्छी बात यह होती है कि हमारे पास बहुत अलग-अलग तरह का कंटेंट ट्राय करने का स्पेस होता है। रीजनल सिनेमा में हमारे पास एक आज़ादी होती है और यही वजह है कि हम बहुत कुछ नया बना सकते हैं। मुझे रीजनल सिनेमा की यह बात बहुत अच्छी लगती है।

हिंदी हो या गुजराती, आपको कई सीनियर एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। आपका कैसा अनुभव रहा?

मुझे जब पता चला कि हीतू कनोडिया (गुजरात सिनेमा के जाने-माने कलाकार) फिल्म में मेरे पिता का रोल अदा करने वाले हैं और फिल्म में हितेन कुमार भी होंगे, तो मैं पहले तो अंदर से हिल गई थी। दरअसल, जब इतने बड़े एक्टर्स आपके साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ता है। ऐसे में मेरे पास भी तब परफॉर्म करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मगर यहां भी मेरी सफलता का क्रेडिट मेरे डायरेक्टर को जाता है जिन्होंने मुझे सिखाने के लिए वर्कशॉप करवाई और कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकती हूं।

अजय देवगन के साथ काम का कैसा एक्सपीरियंस कैसा था?

उनके साथ काम करने का अनुभव भी बहुत बढ़िया रहा। मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि वह मुझे उस स्तर का कम्फर्ट महसूस करवाएंगे, क्योंकि वह मेरी पहली हिंदी फिल्म थी। जिस हिसाब से मुझे वहां लोगों का ट्रीटमेंट मिला, खासकर एक्टर्स से, वह काफी अच्छा और यादगार था। उन्होंने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं एक न्यूकमर हूं। वहां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और इन सभी सीनियर कलाकारों से मिली सीख को मैं अपनी आगे की फिल्मों में अप्लाई करूंगी।

तमिल डेब्यू के लिए परफेक्ट फिल्म है कंचना 4

एक्ट्रेस नोरा फतेही लोकप्रिय तमिल हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'कंचना' के चौथे भाग 'कंचना 4' के साथ तमिल सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं। इस मोस्टअवेटेड फिल्म में नोरा मुख्य भूमिका निभाएंगी। नोरा ने 'कंचना 4' चुनने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा, जब मुझे यह फिल्म ऑफर हुई, तो मुझे लगा कि तमिल सिनेमा में डेब्यू के लिए यह एकदम सही प्रोजेक्ट है। इस फ्रेंचाइजी की पहले से ही मजबूत पहचान है और इसकी अनोखी स्क्रिप्ट ने मुझे आकर्षित किया। नोरा फतेही ने आगे बताया, क्राइम-कॉमेडी ड्रामा मडगांव एक्सप्रेस की सफलता के बाद मैं एक और कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बनना चाहती थी और इस प्रोजेक्ट के साथ मुझे वही रास्ता नजर आया। मैं इस फिल्म में काम करने के लिए बेहद उत्साहित हूं। नोरा ने बताया कि तमिल भाषा सीखना आसान नहीं है। फिल्म के लिए तमिल भाषा सीखना चुनौतीपूर्ण रहा है। उन्होंने बताया, भाषा हमेशा एक चुनौती होती है, लेकिन मुझे चुनौतियां पसंद हैं। मैंने पहले हिंदी, तेलुगू और मलयालम में भी काम किया है और अब तमिल मेरे लिए सबसे मुश्किल भाषा है और इसमें काम करने को लेकर मैं काफी उत्साहित हूं। नोरा फतेही ने यह भी बताया कि वह अपने किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए किस तरह से तैयारी कर रही हैं। उन्होंने बताया, मैं अपने लाइन्स की रिहर्सल करने और उच्चारण पर काम करने के लिए अतिरिक्त समय दे रही हूं। इसके लिए खूब प्रैक्टिस करती हूं। सेट पर मिला प्रोत्साहन सबसे बड़ी प्रेरणा रहा। उन्होंने कहा, क्रू को उम्मीद नहीं थी कि मैं कॉमिक सीन में इतनी सहज रहूंगी। ऐसी प्रतिक्रिया मुझे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। यह संस्कृति और भाषा का सम्मान करने के साथ-साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देने का मौका है। मुझे टीम का भी काफी सपोर्ट मिलता है। नोरा ने तमिल और बॉलीवुड सिनेमा के अंतर को भी रेखांकित किया। उनके मुताबिक, तमिल सिनेमा कहानी और परफॉर्मेंस पर केंद्रित है, जबकि बॉलीवुड की अपनी भव्यता और एनर्जी है। दोनों इंडस्ट्री से सीखना मेरे लिए रोमांचक अनुभव है।

सिद्धार्थ और जाह्नवी हैं परम सुंदरी की परफेक्ट जोड़ी

प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने अपनी आगामी फिल्म परम सुंदरी के बारे में बात करते हुए कहा कि यह फिल्म आधुनिक तकनीक और पारंपरिक जीवन शैली के बीच के अंतर को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में सिद्धार्थ और जाह्नवी को कास्ट करने का कारण उनकी एक-दूसरे से बिल्कुल अलग शख्सियत और उनके किरदारों के साथ उनका तालमेल है।

टेक्नोलॉजी बनाम सादगी: विजन के मुताबिक, परम सुंदरी सिर्फ एक क्रॉस-कल्चरल कहानी नहीं है, बल्कि यह आज के युवाओं की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। फिल्म का नायक परम, एक ऐसा किरदार है जो टेक्नोलॉजी और ऐप्स पर पूरी तरह निर्भर है। वहीं, सुंदरी का किरदार एक ऐसी दुनिया से आता है जहाँ जीवन बहुत सरल और तकनीक के प्रभाव से दूर है। विजन ने कहा, फिल्म की कहानी यही संदेश देती है कि आज के युवा हर काम के लिए ऐप्स पर निर्भर हैं, और इस वजह से वे असली और ऑर्गेनिक रिश्तों की खूबसूरती को भूलते जा रहे हैं।

कास्टिंग पर विजन के विचार: दिनेश विजन ने सिद्धार्थ और जाह्नवी की कास्टिंग को लेकर कहा कि सिद्धार्थ एक हैंडसम हीरो हैं, लेकिन उन्होंने पिछले छह सालों में कोई रोमांटिक-कॉमेडी नहीं की है। वहीं, जाह्नवी, जो असल जिंदगी में सुंदरी जैसी ही हैं, ने भी ऐसा रोल पहले कभी नहीं निभाया।

नुसरत भरूचा की उफ्फ ये सियापा में दिखेगी बिना डायलॉग डार्क कॉमेडी

नुसरत भरूचा की फिल्म 'उफ्फ ये सियापा' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। बता दें ये फिल्म बिना डायलॉग के एक डार्क कॉमेडी है, जिसमें हर सीन सिर्फ हावभाव और एक्सप्रेशन से कहानी कहता है। फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

फिल्म की कहानी घूमती है केसरी लाल सिंह (सोहम शाह) के इर्द-गिर्द, जो एक साधारण और भोला-भाला इंसान है। उसकी पत्नी पुष्पा (नुसरत) उसे पड़ोसन कमिनी (नोरा फतेही) से फ्लर्ट करने का इल्जाम लगाकर घर छोड़ देती है। जैसे ही वह अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, अचानक उसके घर एक लाश मिलती है। मामला यहीं नहीं रुकता, थोड़ी देर में दूसरी लाश भी सामने आ जाती है और केसरी की जिंदगी पूरी तरह उलझ जाती है। इस गड़बड़झाले में इंस्पेक्टर हसमुख (ओमकार कपूर) की एंट्री होती है, जो खुद भी अपने मकसद से कहानी में रंग भरता है।

फिल्म में सोहम शाह, नुसरत भरूचा और नोरा फतेही मुख्य भूमिकाओं में हैं। सोहम शाह अपनी सीरियस एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनकी मासूमियत और बेबस कॉमिक टाइमिंग दिल जीत सकती है। नुसरत भरुचा के लिए यह साल खास है क्योंकि यह उनकी दूसरी फिल्म है 'छोरी 2' के बाद। वहीं नोरा फतेही भी 2025 में तीसरी बार बड़े पर्दे पर दिखाई देंगी। हाल ही में वो अभिषेक बच्चन की 'बी हैप्पी' और कन्नड़ थ्रिलर 'केडी - द डेविल' में नजर आ चुकी हैं। 'उफ्फ ये सियापा' का निर्देशन जी. अशोक ने किया है और इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। संगीत की जिम्मेदारी ए.आर. रहमान ने उठाई है, हालांकि यह फिल्म गानों से नहीं बल्कि बैकग्राउंड स्कोर और साउंड इफेक्ट्स से दर्शकों पर असर डालेगी। अभिनेता शारीब हाशमी भी एक अहम किरदार में नजर आएंगे।

विक्रम भट्ट के एक और प्रोजेक्ट में सनी लियोनी की एंट्री

सनी लियोनी ने जिस्म 2, रईस, तेरा इंतजार और एक पहेली लीला जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। वेब सीरीज में भी वे नजर आ चुकी हैं। पोस्ट शेयर कर उन्होंने अपने आगामी प्रोजेक्ट पर डिटेल शेयर की हैं, जिसकी शूटिंग शुरू कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें वे निर्देशक विक्रम भट्ट के साथ काम करेंगी।

सनी ने जताई विक्रम भट्ट के साथ काम करने की खुशी

सनी लियोनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें वे निर्देशक विक्रम भट्ट के साथ नजर आ रही हैं।सनी ने इसके साथ कैप्शन लिखा है, अपने पसंदीदा निर्देशकों में से एक के साथ फिर से काम करने का मौका मिला है। चलिए कुछ जादू करते हैं।

सीरीज अनामिका में साथ कर चुके हैं काम

बता दें कि इससे पहले सनी लियोनी विक्रम भट्ट के साथ वेब सीरीज अनामिका में काम कर चुकी हैं, जो साल 2022 में आई थी। एक्शन से भरपूर यह जासूसी थ्रिलर वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर पर उपलब्ध है। इसका निर्देशन विक्रम भट्ट ने किया।

नेटिजन्स ने दी बधाई

सनी और विक्रम के आगामी प्रोजेक्ट को लेकर नेटिजन्स रिएक्शन दे रहे हैं। दोनों को बधाई दे रहे हैं। सनी लियोनी के बॉलीवुड करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2012 में आई फिल्म जिस्म 2 से डेब्यू किया था। हालांकि, वो साल 2011 में ही चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस में आकर भारत में अपनी पहचान बना चुकी थीं। सनी का असली नाम करनजीत कौर वोहरा था, लेकिन एडल्ट इंडस्ट्री में काम करने के लिए उन्होंने अपना नाम सनी लियोनी रख लिया।

सलमान खान ही नहीं, शिल्पा शेट्टी से लेकर संजय दत्त तक; ये सेलेब भी रहे 'बिग बॉस' के होस्ट

बहुचर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 19, 24 अगस्त से शुरू हो गया है। ये नया सीजन भी पिछले कई साल की तरह ही सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2000 में शुरू हुए इस शो को अभी तक कुल छह होस्ट मिल चुके हैं। हालांकि, इन सभी होस्ट में सलमान को दर्शकों द्वारा खूब प्यार मिला। आइए जानते हैं कि बिग बॉस को अभी तक किन-किन सेलेब्स ने होस्ट किया है।

अरशद वारसी

बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता अरशद वारसी साल 2006 में बिग बॉस के पहले सीजन के होस्ट रहे थे। ये कह सकते हैं कि इस शो की शुभ शुरुआत अरशद वारसी ने ही की थी।

शिल्पा शेट्टी

बिग बॉस सीजन 2 की होस्ट बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी थीं। इस शो को काफी लोकप्रियता मिली थी। एक्ट्रेस के मजाकिया अंदाज और शानदार कलाकारी को दर्शकों ने पसंद किया था। शो के बीच में एक्ट्रेस की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें शो छोड़ना पड़ा।

अमिताभ बच्चन

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। शिल्पा शेट्टी द्वारा बिग बॉस सीजन 2 बीच में ही छोड़ने के कारण अमिताभ बच्चन ने इसे होस्ट किया था। अभिनेता उस समय कौन बनेगा करोड़पति शो के जरिए लोगों के दिलों में जगह बना चुके थे। बिग बॉस में भी बिग बी ने शानदार काम किया।

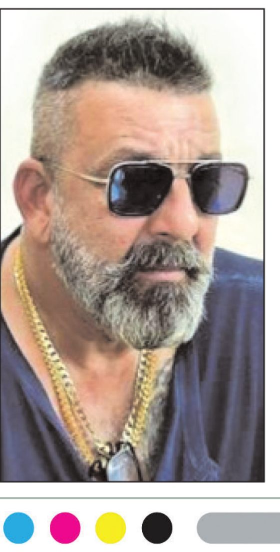

संजय दत्त

बिग बॉस सीजन पांच में सलमान खान होस्ट थे, लेकिन उनके साथ संजय दत्त भी बतौर होस्ट शामिल हुए थे। दोनों अभिनेताओं की जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था।

फराह खान

बिग बॉस सीजन 8 में निर्देशक-कोरियोग्राफर फराह खान बतौर होस्ट शो के बीच में शामिल हुई थी। वजह थी कि सलमान खान को बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग करने के कारण ब्रेक लेना पड़ा था। फराह खान के अंदाज को भी दर्शकों ने पसंद किया था।

सलमान खान

शो को अभी तक सलमान खान के अलावा पांच होस्ट मिले, लेकिन दर्शकों ने जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया वो सलमान खान हैं। अभिनेता सीजन 9 से लगातार बिग बॉस शो को होस्ट कर रहे हैं। आज रविवार से बिग बॉस 19 शुरू हो रहा है, जिसका दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है।

साभार एजेंसी

गंभीर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाई कोर्ट ने इस मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली उच्च न्यायालय पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान मुख्य कोच गौतम गंभीर के खिलाफ निचली अदालती कार्यवाही रोकने की याचिका से सहमत नहीं है। गंभीर, उनके फाउंडेशन और परिवार के सदस्यों पर अवैध रूप से कोविड-19 की दवाइयां वितरित करने के आरोप हैं। गंभीर के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की याचिका दायर की गई थी। हालांकि न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने दृढ़ता से कहा कि अदालत इस अनुरोध पर विचार करेगी। न्यायाधीश ने कहा, अगर आपने एक साधारण अनुरोध किया होता, तो मैं उस पर विचार करती। आप मुझे बहुत सी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले (पार्टी का) नाम, उनकी साख, उनके द्वारा किए गए कार्य। आप नाम उछालने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि यह अदालत में काम करेगा। यह काम नहीं करता। अदालत की सुनवाई 8 सितंबर को होनी थी। यह भी कहा गया कि पूर्व सांसद और क्रिकेटर ने लॉकडाउन के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां दान की थीं। हालांकि, उच्च न्यायालय अपने मूल रुख से पीछे नहीं हटा। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार स्थगन आदेश लागू हो जाने पर सुनवाई तुरंत रुक जाती है, जांच रुक जाती है और पूरा मामला अंततः खारिज हो जाता है। यह शिकायत मूल रूप से औषधि नियंत्रण विभाग (डीसीडी) द्वारा गंभीर और उनके फाउंडेशन गौतम गंभीर फाउंडेशन और सीईओ अपराजिता सिंह के खिलाफ दर्ज की गई थी। उनकी मां (सीमा गंभीर) और पत्नी (नताशा गंभीर) को भी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं के रूप में नामित किया गया है।

जॉन मूनी 6 साल बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी, एशिया कप से पहले मिली बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली, एजेंसी। आयरलैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जॉन मूनी छह साल के अंतराल के बाद अफगानिस्तान की राष्ट्रीय टीम में वापसी कर रहे हैं। बुधवार को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की कि मूनी को उनकी राष्ट्रीय टीम का नया फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है। मूनी ने 2018 से 2019 तक अफगानिस्तान के साथ काम किया था, को शेन मैकडरमॉट के जाने के बाद यह पद खाली होने पर नियुक्त किया गया था। मैकडरमॉट वर्तमान में पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच के रूप में मार्गदर्शन कर रहे हैं। मूनी ने 91 अंतरराष्ट्रीय मैचों में आयरलैंड का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 2007, 2011 और 2015 के तीन आईसीसी क्रिकेट विश्व कप और दो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप शामिल हैं। उनके पास इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड से लेवल 3, 2 और 1 कोचिंग सर्टिफिकेट हैं। अफगानिस्तान के साथ काम करने के अलावा मूनी ने 2019 में वेस्टइंडीज के साथ और इस साल जनवरी से आयरलैंड की महिला टीम के साथ भी काम किया है। ACB ने ऑस्ट्रेलिया के निर्मलन थानाबालासिंगम को अपना नया फिजियोथेरेपिस्ट भी नियुक्त किया है। थानाबालासिंगम फिजियोथेरेपी और खेल विज्ञान में एक मजबूत शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि लेकर आए हैं। उन्होंने 2010 में फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, और 2008 में सिडनी विश्वविद्यालय से व्यायाम और खेल विज्ञान में अनुप्रयुक्त विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह ऑस्ट्रेलिया के फिजियोथेरेपी बोर्ड में एक पंजीकृत चिकित्सक और ऑस्ट्रेलियाई फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के एक सक्रिय सदस्य हैं। अफगानिस्तान वर्तमान में अबु धाबी में एक प्रशिक्षण और तैयारी शिविर में भाग ले रहा है, जहां वे त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान और मेजबान संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं, साथ ही पुरुष टी20 एशिया कप 2025 भी शामिल है।

कैरेबियन लीग में एक बॉल पर बने 22 रन, नो, वाइड, फिर लगातार 2 नो बॉल पर 2 सिक्स; अगली बॉल पर भी सिक्स

नई दिल्ली, एजेंसी। कैरेबियन प्रीमियर लीग में सोमवार रात एक बॉल पर 22 रन बने। मामला सेंट लूसिया ग्राउंड पर गयाना अमेजन वॉरियर्स और सेंट लूसिया किंग्स के बीच खेले गए मैच का है। टॉस जीतकर गयाना अमेजन वॉरियर्स पहले बैटिंग कर रही थी। रोमारियो शेफर्ड और इफ्तिखार अहमद क्रीज पर थे। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर 22 रन बने। ओशाने थॉमस ने ओवर की तीसरी गेंद नो बॉल डाली। इस पर बल्लेबाज और कोई रन नहीं बना सका। उन्होंने अगली गेंद वाइड डाली। फिर अगली दो गेंदें नो बॉल डाली। इन दोनों गेंदों पर बल्लेबाज शेफर्ड ने दो छक्के जड़ दिए। थॉमस ने अगली गेंद सही डाली। इस पर भी शेफर्ड ने छक्का जड़ दिया। इस तरह तीसरी गेंद पर कुल 22 रन बन गए। इसकी डिटेल्स अगले ग्राफिक्स में देख सकते हैं।

भारत की 17 साल की कोयल बार का जलवा

अहमदाबाद, एजेंसी। 17 साल की कोयल ने गजब का जज्बा दिखाते हुए तब सुर्खियां बटोरीं, जब बिंदियारानी और मुथुरमुथुपंडी राजा जैसे भारोत्तोलक पदक जीतने में सफल रहे। कोयल को आने वाले समय का स्टार माना जा रहा है। 17 साल की भारतीय भारोत्तोलक कोयल बार ने मंगलवार को यहां राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में महिलाओं की 53 किग्रा स्पर्धा में दो नए युवा विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके युवा और जूनियर दोनों खिताब जीते। जूनियर और युवा दोनों वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए इस किशोरी ने कुल 192 किग्रा (85 किग्रा + 107 किग्रा) वजन उठाया। उन्होंने पहले 85 किग्रा भार उठाकर युवा स्नैच विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर क्लीन एंड जर्क में अपने दूसरे प्रयास में 107 किग्रा भार उठाकर 105 किग्रा के रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। इसके साथ ही, उन्होंने 188 किग्रा के मौजूदा युवा विश्व कुल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया।

कोयल का प्रयास स्नेहा से बेहतर

कोयल का प्रयास उनकी हमवतन स्नेहा सोरेन से तीन बेहतर था, जिन्होंने 185 किग्रा (81 किग्रा + 104 किग्रा) के साथ सीनियर वर्ग में रजत पदक जीता था। इससे पहले महिलाओं में भारत की बिंदियारानी देवी और पुरुषों में मुथुपंडी राजा ने मंगलवार को अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि, सारी सुर्खियां गजब का जज्बा दिखाने वाली 17 वर्षीय कोयल ने बटोरीं।

बिंदियारानी को मिला पदक

महिलाओं के 58 किग्रा वर्ग में भाग लेने वाली बिंदियारानी ने 206 किग्रा (91 किग्रा स्नैच + 115 किग्रा क्लीन एंड जर्क) भार उठाकर रजत पदक जीता।

उन्होंने स्नैच में 85 किग्रा, 88 किग्रा और 91 किग्रा भार उठाया और क्लीन एंड जर्क में 110 किग्रा और 115 किग्रा भार उठाया। वह अपने अंतिम 122 किग्रा प्रयास में असफल रहीं और दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कियाना इलियट ने 212 किग्रा (100 किग्रा + 112 किग्रा) के साथ स्वर्ण पदक जीता। बिंदियारानी बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किग्रा वर्ग में रजत पदक विजेता हैं। वह पूर्व राष्ट्रमंडल चैंपियन भी हैं, जिन्होंने 2019 में स्वर्ण और 2021 संस्करणों में रजत पदक जीता है।

मुथुपंडी ने भी जीता पदक

पुरुष वर्ग की बात करें तो, मुथुपंडी राजा 65 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक के बेहद करीब पहुंच गए, लेकिन 296 किग्रा (128 किग्रा+168 किग्रा) वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। मलयेशिया के मुहम्मद अजनिल बिन बिदिन ने 297 किग्रा (125 किग्रा+172 किग्रा) वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। पापुआ न्यू गिनी के मोरिया बारू 292 किग्रा (127 किग्रा+165 किग्रा) वजन उठाकर कांस्य पदक जीतने में सफल रहे।

300 से ज्यादा एथलीट्स

टूर्नामेंट के 30वें संस्करण में 31 देशों के 300 से ज्यादा भारोत्तोलक हिस्सा ले रहे हैं। टोक्यो 2020 की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने सोमवार को महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक के साथ भारत के अभियान की शुरुआत की थी और अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया था।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बाद अश्विन ने आईपीएल से भी संन्यास लिया

नई दिल्ली, एजेंसी। दिग्गज क्रिकेटर आर अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बाद आईपीएल से भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अश्विन ने सोशल मीडिया के माध्यम से आईपीएल को अलविदा कहने की सूचना दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अश्विन ने लिखा, खास दिन और इसलिए एक खास शुरुआत। कहते हैं हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है। लेकिन, विभिन्न लीगों में खेलने की संभावनाएं आज से शुरू हो रही हैं। इतने सालों की शानदार यादों और रिश्तों के लिए सभी फ्रेंचाइजी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आईपीएल और बीसीसीआई का विशेष तौर पर शुक्रिया।

आगे जो भी है उसका आनंद लेने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए उत्सुक हूं। आईपीएल 2025 में अश्विन सीएसके का हिस्सा थे। टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। ऐसे में अगले सीजन में टीम बड़े बदलावों के साथ उतर सकती हैं। अश्विन के सोशल मीडिया पोस्ट से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह बेशक आईपीएल में खेलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन दूसरी क्रिकेट लीग में खेलते हुए वह दिख सकते हैं। संभवतः वह देश के बाहर खेली जाने वाली टी20 लीग में खेलते दिख सकते हैं। गौरतलब है कि बीसीसीआई भारत के अंतरराष्ट्रीय या घरेलू क्रिकेट से जुड़े किसी भी मौजूदा खिलाड़ी को विदेशी टी20 लीग में खेलने की छूट नहीं देता है। हालांकि, अब अश्विन संन्यास के बाद इन लीग में खेल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की तरह अश्विन का आईपीएल करियर भी शानदार रहा है। 2008 से 2025 के बीच वह चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपर जाइंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे हैं। पंजाब किंग्स के वह कप्तान भी रहे हैं। 220 आईपीएल मैचों की 98 पारियों में 833 रन बनाने वाले अश्विन ने 187 विकेट लिए हैं। आईपीएल इतिहास के वह पांचवें सफलतम गेंदबाज हैं। अश्विन ने दिसंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। आर अश्विन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बेहद यादगार रहा है। उनका नाम विश्व के श्रेष्ठतम ऑफ स्पिनर्स में शुमार किया जाता है। 2010 से 2024 के बीच 106 टेस्ट में 537 विकेट, 116 वनडे में 156 विकेट और 65 टी20 में 72 विकेट उनके नाम दर्ज हैं। टेस्ट क्रिकेट में अश्विन एक बल्लेबाज के रूप में भी सफल रहे हैं। 6 शतक और 14 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 3,503 रन बनाए हैं।

FIDE World Cup: 23 साल बाद भारत में होगा फिडे विश्व कप का आयोजन

नई दिल्ली, एजेंसी। इस टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश, मैग्नस कार्लसन, फाबियानो करुआना और आर प्रज्ञानानंदा सहित 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि दो दशक से अधिक समय के बाद प्रतिष्ठित फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी करना भारत के लिए प्रसन्नता की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि शतरंज युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस टूर्नामेंट में रोमांचक मैच देखने को मिलेंगे और दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, प्रतिष्ठित फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी करना भारत के लिए प्रसन्नता की बात है और वह भी दो दशक से अधिक समय के बाद। फिडे शतरंज विश्व कप का आयोजन गोवा में 30 अक्तूबर से 27 नवंबर तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में अगले साल के कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए तीन स्थान और 20 लाख डॉलर की इनामी राशि दांव पर लगी होगी। इस टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश, मैग्नस कार्लसन, फाबियानो करुआना और आर प्रज्ञानानंदा सहित 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत के लिए यह बड़ा अवसर है क्योंकि 23 साल बाद पहली बार देश में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। पिछली बार 2002 में हैदराबाद में भारत ने इस प्रतियोगिता की मेजबानी की थी और तब विश्वनाथन आनंद ने खिताब जीता था।

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में शतरंज में काफी तरक्की की है। यह टूर्नामेंट आठ दौर में दो बाजियों के नॉकआउट प्रारूप में खेला जाएगा। दो क्लासिकल बाजियां होंगी जिनमें बराबरी पर रहने पर रैपिड और ब्लिट्ज प्लेऑफ होंगे।

Football: भारतीय फुटबॉल महासंघ पर फिर मंडराया प्रतिबंध का खतरा

नई दिल्ली, एजेंसी। यह पहली बार नहीं है जब भारतीय फुटबॉल को इस तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अगस्त 2022 में फीफा ने भारत को 'तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप' के आरोप में निलंबित कर दिया था। भारतीय फुटबॉल पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि वैश्विक संचालन संस्था फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) ने संकटग्रस्त अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को सख्त चेतावनी दी है कि उसे 30 अक्तूबर तक नया संविधान अपनाना और उसकी पुष्टि करनी होगी या फिर निलंबन का जोखिम उठाना पड़ेगा। एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे को मंगलवार को लिखे दो पन्नों के कड़े पत्र में दोनों अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने 2017 से उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद महासंघ द्वारा अपने संविधान

को अंतिम रूप देने में विफलता पर 'गहरी चिंता' व्यक्त की। शीर्ष अदालत गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।

निलंबन का क्या मतलब?

निलंबन का मतलब होगा कि राष्ट्रीय टीमों और क्लबों को सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और साथ ही अहमदाबाद में 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए भारत की महत्वाकांक्षी बोली भी अनिश्चितता में पड़ जाएगी। फीफा और एएफसी ने चौबे के नेतृत्व वाले एआईएफएफ को संशोधित संविधान को मंजूरी देने के लिए उच्चतम न्यायालय से एक 'निश्चित आदेश' प्राप्त करने, इसे फीफा और एएफसी के अनिवार्य नियमों के अनुरूप बनाने और 30 अक्तूबर की समय-सीमा से पहले अगली आम सभा की बैठक में इसकी पुष्टि करने का निर्देश दिया है।

पत्र में कहा गया है, इस कार्यक्रम का पालन नहीं करने पर हमारे पास इस मामले को निर्णय लेने वाली फीफा की संबंधित संस्था के पास विचार और निर्णय के लिए भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगाज जिसमें निलंबन की संभावना भी शामिल है। इस पत्र पर फीफा के मुख्य सदस्य संघ अधिकारी एल्खान मामादोव और एएफसी के उप महासचिव (सदस्य संघ) वाहिद कर्दानी ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं।

अनीष भानवाला के हाथों से छूटा गोल्ड, एशियाई चैंपियनशिप में जीता रजत पदक

शिमकेंट (कजाखस्तान), एजेंसी। भारतीय निशानेबाज अनीष भानवाला ने बुधवार को यहां एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष 25 मीटर रेपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का रजत पदक जीता। 22 साल के अनीष स्वर्ण पदक की दौड़ में सिर्फ एक अंक से चूक गए। उन्होंने 35 अंक जुटाए जो स्वर्ण पदक विजेता चीन के शु लियानबोफान से एक अंक कम रहा। कांस्य पदक कोरिया के ली जेइकयून ने जीता। अनीष शुरुआती चार सीरीज के बाद एक अंक से आगे चल रहे थे लेकिन इसके बाद पिछड़ गए। मंगलवार को ओलंपियन सिफत कौर सामरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने के अलावा देश को टीम खिताब भी दिलाया। भारत ने प्रतियोगिता में अब तक 72 पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में जूनियर स्पर्धाएं भी हो रही हैं। जूनियर निशानेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने अब तक 39 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं।

यूएस ओपनः वीनस विलियम्स और लेयला फर्नांडीज के बीच होगा महिला युगल मैच

न्यूयॉर्क, एजेंसी। यूएस ओपन महिला एकल में पहले राउंड से ही बाहर हुई वीनस विलियम्स का अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है। वीनस महिला युगल में लेयला फर्नांडीज के साथ खेलती हुई दिखेंगी। उन्हें वाइल्ड-कार्ड एंट्री दी गई है।

वीनस विलियम्स और लेयला फर्नांडीज का मुकाबला छठी वरीयता प्राप्त यूक्रेन की ल्यूडमिला किचेनोक और ऑस्ट्रेलिया की एलेन पेरेज की जोड़ी से होगा। 22 वर्षीय फर्नांडीज को न्यूयॉर्क में महिला एकल में 31वीं वरीयता दी गई है और उन्होंने पहले दौर में हमवतन रेबेका मैरिनो को 6-2, 6-1 से हराया। वह 2021 में एकल फाइनल में पहुंचीं, जहां

वह ब्रिटेन की एम्मा राडुकानू से उपविजेता रहीं। 45 साल की वीनस 2 साल में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। वीनस विलियम्स महिला युगल की सफलतम खिलाड़ियों में से एक हैं। अपनी बहन सेरेना विलियम्स के साथ उन्होंने 14 ग्रैंड स्लैम महिला युगल खिताब जीते हैं। आखिरी बार 2016 में उन्होंने विंबलडन जीता था। महिला युगल में वह आखिरी बार 2022 में सेरेना विलियम्स के साथ यूएस ओपन में दिखी थी। वह सेरेना का विदाई टूर्नामेंट था। 2025 यूएस ओपन में, विलियम्स पहले ही महिला एकल और मिश्रित युगल (रीली ओपेल्का के साथ) में भाग ले चुकी हैं। सोमवार रात, उन्होंने आर्थर ऐश स्टेडियम में एक रोमांचक दूसरे सेट में जीत हासिल की, लेकिन अंततः 11वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना मुचोवा से 6-3, 2-6, 6-1 से हार गईं। 1981 में रेनी रिचर्ड्स के बाद विलियम्स यहां महिला एकल में प्रतिस्पर्धा करने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थीं और ओपन एरा की तीसरी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थीं।

विलियम्स और फर्नांडीज महिला युगल ड्रॉ में सात वाइल्ड-कार्ड टीमों में शामिल हैं, जिनमें हैली बैप्टिस्ट और व्हिटनी ओसुइग्वे, रीज ब्रैंटमेयर और एलानिस हैमिल्टन, कारमेन कॉर्ली और इवाना कॉर्ली, क्रिस्टीना पेनिकोवा और थिया फ्रोडिन, क्लर्वी न्गोउए और इवा जोविक, और जूलियट पारेजा और आकाश उरहोबो शामिल हैं। 2025 यूएस ओपन महिला युगल प्रतियोगिता गुरुवार को यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में शुरू होगी।

"बिहार NDA सीट बंटवारा फाइनल: जेडीयू 102, भाजपा 101 और चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीटें"

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं और खींचतान के बाद आखिरकार नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (NDA) में सीटों के बंटवारे की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया दिल्ली दौरे के बाद गठबंधन के भीतर अंतिम सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक, जनता दल यूनाइटेड (JDU) को 102, भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 101, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) यानी LJP(R) को 20, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (HAM) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को 10-10 सीटें दी गई हैं। इस तरह 243 विधानसभा सीटों पर NDA का बंटवारा तय हो गया है।

NDA में खींचतान के बाद बनी सहमति

पिछले कुछ महीनों से बिहार NDA में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी थी। खासकर JDU और BJP के बीच सीटों के अनुपात को लेकर कई दौर की बातचीत हुई। दोनों ही दल राज्य में बराबर की ताकत दिखाना चाहते थे। हालांकि, अंततः इस फार्मूले पर सहमति बनी कि JDU को भाजपा से एक सीट ज्यादा दी जाएगी। यही कारण है कि JDU को 102 और भाजपा को 101 सीटें मिली हैं। वहीं, चिराग पासवान की पार्टी LJP(R) को 20 सीटें देकर NDA ने दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। चिराग पासवान पिछले कुछ समय से लगातार सक्रिय हैं और खुद को बिहार की राजनीति में मजबूत नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। उनके पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए NDA ने उन्हें सम्मानजनक सीटें दी हैं।

छोटे दलों को भी जगह

NDA ने इस बार छोटे दलों को भी अनदेखी नहीं की है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (HAM) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को 10-10 सीटें देकर गठबंधन ने संदेश दिया है कि सामाजिक समीकरण साधने के लिए सभी दलों को साथ रखा जाएगा। मांझी जहां महादलित समुदाय में अपनी पकड़ रखते हैं, वहीं कुशवाहा ओबीसी वर्ग, खासकर कुशवाहा समाज के बीच मजबूत प्रभाव रखते हैं। ऐसे में NDA ने सीट बंटवारे में इन्हें संतुलनकारी भूमिका दी है।

आधिकारिक ऐलान बाकी

हालांकि, सीट बंटवारे को लेकर अभी तक NDA की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन की ओर से इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही यह भी बताया जाएगा कि कौन सी पार्टी किन-किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल सीटों की अदला-बदली को लेकर भी चर्चा जारी है। सूत्रों का कहना है कि 1-2 सीटों पर JDU और BJP में बदलाव संभव है, लेकिन कुल सीटों का अनुपात तय हो चुका है।

राजनीतिक समीकरण और चुनौतियां

बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरण और गठबंधनों पर आधारित रही है। NDA की इस सीट शेयरिंग को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की JDU और भाजपा दोनों ही राज्य में बड़ी ताकतें हैं। लेकिन विपक्ष में महागठबंधन (RJD, कांग्रेस और वाम दल) भी मजबूती से मैदान में है। इस बार NDA के सामने सबसे बड़ी चुनौती एंटी-इनकंबेंसी (विरोधी लहर) की मानी जा रही है। नीतीश कुमार लंबे समय से सत्ता में हैं और विपक्ष लगातार उनकी नीतियों और कामकाज को मुद्दा बना रहा है। वहीं, भाजपा की कोशिश रहेगी कि केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाकर राज्य में जीत दर्ज की जाए।

चिराग पासवान की भूमिका अहम

इस चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका अहम मानी जा रही है। 20 सीटें मिलने के बाद वे गठबंधन में तीसरी बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। उनके सामने अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की चुनौती होगी। वे खुद को बिहार की राजनीति में युवा चेहरे और दलित नेतृत्व के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं।

क्या कहता है समीकरण?

243 सीटों वाले बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है। NDA ने इस बार सभी दलों को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। JDU और BJP के बीच सीटों का लगभग बराबर बंटवारा इस बात का संकेत है कि दोनों दल गठबंधन में बराबरी बनाए रखना चाहते हैं। वहीं, छोटे दलों को भी पर्याप्त जगह देकर NDA ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कोई भी साथी उपेक्षित नहीं रहेगा।

नतीजों पर पड़ सकता है असर

NDA के इस बंटवारे से आगामी चुनावों में कई सीटों पर असर पड़ सकता है। भाजपा और JDU का संयुक्त वोट बैंक काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में RJD भी दमखम से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में मुकाबला कांटे का हो सकता है। बिहार NDA की सीट शेयरिंग से यह साफ हो गया है कि गठबंधन ने आंतरिक खींचतान को खत्म कर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। JDU को 102 और भाजपा को 101 सीटें देकर संतुलन साधा गया है, वहीं चिराग पासवान और अन्य छोटे दलों को भी सम्मानजनक हिस्सेदारी दी गई है।

केजरीवाल बोले- मोदी सरकार का अमेरिकी कपास पर टैक्स हटाने का फैसला

-किसानों के लिए झटका या इंडस्ट्री की मजबूरी?

नई दिल्ली। देश की सियासत एक बार फिर किसानों और विदेशी व्यापार नीति के बीच उलझ गई है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कपास पर लगने वाला 11% इम्पोर्ट टैक्स हटाकर भारतीय किसानों के साथ धोखा किया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज़ में यह स्पष्ट किया गया कि अमेरिकी कपास को टैक्स फ्री करने की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। वित्त मंत्रालय का तर्क है कि यह फैसला घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड पूरी करने के लिए लिया गया है, ताकि उद्योग को कच्चे माल की कमी न झेलनी पड़े।

केजरीवाल के आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि यह फैसला सीधे-सीधे भारतीय किसानों के खिलाफ है। उनके मुताबिक— जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगाया है, तब भारत को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार को चाहिए था कि वह अमेरिकी सामानों पर 100% तक टैक्स बढ़ाए, ताकि अमेरिका को सबक मिले। इसके बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कपास को टैक्स फ्री कर दिया, जिससे भारत के कपास किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नीति किसानों को आत्महत्या करने तक मजबूर कर सकती है, क्योंकि घरेलू मंडियों में कपास की कीमतें गिर जाएंगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यह फैसला बताता है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता विदेशी दबाव और बड़े उद्योगपतियों का हित है, न कि देश के अन्नदाता किसान।

केंद्र सरकार का बचाव

केंद्र ने अपने बचाव में कहा कि— भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और यह लाखों लोगों को रोजगार देती है। हाल के वर्षों में घरेलू कपास उत्पादन कम हुआ है और उद्योग को कच्चे माल की कमी झेलनी पड़ रही है। ग्लोबल कॉटन मार्केट में कीमतें बढ़ने से कपड़ा उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा है। अगर उद्योग को सस्ता कपास नहीं मिलेगा तो एक्सपोर्ट घटेगा और रोजगार पर असर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि अमेरिकी कपास पर टैक्स छूट स्थायी नहीं है, बल्कि केवल 31 दिसंबर तक दी गई है।

किसानों की स्थिति

भारत दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में से एक है। खासकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और मध्य प्रदेश में लाखों किसान कपास की खेती पर निर्भर हैं। पिछले कुछ सालों में कपास की कीमतों में उतार-चढ़ाव से किसान पहले ही परेशान हैं। अगर अमेरिकी कपास टैक्स फ्री होकर बड़े पैमाने पर भारत आएगा तो स्थानीय किसानों की फसल के दाम गिर सकते हैं। मंडियों में पहले से ही मांग और आपूर्ति का असंतुलन किसानों को घाटे में डाल रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) मजबूत करना चाहिए, ताकि उन्हें नुकसान न उठाना पड़े।

इंडस्ट्री बनाम किसान: दो ध्रुवों की खींचतान

यह मसला दरअसल दो अलग-अलग हित समूहों की खींचतान बन चुका है— किसान, जिन्हें अपनी फसल का वाजिब दाम चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसे सस्ता कच्चा माल चाहिए ताकि वह वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके। सरकार का झुकाव फिलहाल इंडस्ट्री की ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि लंबे समय तक यह नीति किसानों को हाशिए पर धकेल सकती है।

राजनीतिक मायने

यह विवाद सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। किसानों का भरोसा जीतना हर पार्टी के लिए अहम है, खासकर तब जब देश कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है। केजरीवाल ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब विपक्ष मोदी सरकार को अमेरिका से रिश्तों और व्यापारिक समझौतों को लेकर लगातार घेर रहा है।

आगे का रास्ता

विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद का हल एक संतुलित नीति से ही निकल सकता है। सरकार को चाहिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मांग भी पूरी करे और किसानों को भी उचित दाम की गारंटी दे। MSP को कानूनी गारंटी देना और कपास किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज लाना जरूरी है। साथ ही, लंबे समय के लिए भारत को कपास उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, ताकि विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो। अमेरिकी कपास पर टैक्स हटाने का फैसला फिलहाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हित में है, लेकिन इसके चलते किसानों में असंतोष बढ़ना तय है। केजरीवाल के आरोपों ने इस फैसले को राजनीतिक बहस का हिस्सा बना दिया है।

ममता बनर्जी का ऐलान: भाजपा का भाषायी आतंक बर्दाश्त नहीं

बोली- मताधिकार छीनने नहीं दूंगी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भाजपा पर सीधा हमला बोला है। कोलकाता में तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) के स्थापना दिवस के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने भाजपा पर मतदाताओं को अधिकारों से वंचित करने की साजिश का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि भाजपा बंगालियों के खिलाफ "भाषायी आतंक" फैला रही है और मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाने की कोशिश कर रही है।

भाजपा पर गंभीर आरोप

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि भाजपा ने दूसरे राज्यों से 500 से ज्यादा टीमें बंगाल भेजी हैं। ये टीमें कथित तौर पर ऐसे सर्वे करा रही हैं, जिनके आधार पर मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। ममता ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे खुद जाकर सुनिश्चित करें कि उनका नाम मतदाता सूची में बना हुआ है या नहीं।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा— "जब तक मैं जिंदा हूं, किसी को भी मताधिकार छीनने नहीं दूंगी। वोट देना हर नागरिक का अधिकार है और इसे छीनने का प्रयास लोकतंत्र पर सीधा हमला है।"

भाषायी आतंक का मुद्दा

मुख्यमंत्री ने "भाषायी आतंक" शब्द का इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल में बंगाली भाषा और संस्कृति को निशाना बना रही है। उनका कहना था कि भाजपा की कोशिश है कि बंगालियों को हाशिये पर धकेला जाए और उन्हें चुनावी प्रक्रिया से दूर किया जाए। ममता ने कहा कि बंगालियों की अपनी अस्मिता और अधिकारों की रक्षा करनी होगी।

चुनाव आयोग पर सवाल

ममता ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग राज्य के अधिकारियों को धमका रहा है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग का अधिकार केवल चुनावी अवधि, यानी लगभग तीन महीनों तक सीमित है। सालभर राज्य सरकार के कामकाज में दखल देना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

लोकतंत्र की रक्षा की अपील

ममता बनर्जी ने अपने भाषण में युवाओं और छात्रों से भी अपील की कि वे लोकतंत्र और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की इन नीतियों को समय रहते रोका नहीं गया तो आने वाली पीढ़ियां अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित हो सकती हैं।

तृणमूल कांग्रेस का रुख

टीएमसी लगातार भाजपा पर "बाहरी राजनीति" करने और बंगाल की संस्कृति को कमजोर करने के आरोप लगाती रही है। ममता का यह बयान उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि वे किसी भी कीमत पर भाजपा की इस रणनीति को सफल नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी का यह बयान केवल भाजपा की आलोचना नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में बढ़ते तनाव और ध्रुवीकरण की झलक भी देता है। एक ओर भाजपा बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं ममता खुद को बंगाल की अस्मिता और लोकतांत्रिक अधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक के रूप में पेश कर रही हैं। आने वाले चुनावों में यह टकराव और गहराएगा, और मतदाता सूची को लेकर उठे विवाद बंगाल की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है।

ट्रम्प सलाहकार का विवादित बयान : यूक्रेन जंग को बताया "मोदी वॉर"

-भारत पर रूस-चीन से नजदीकी का आरोप

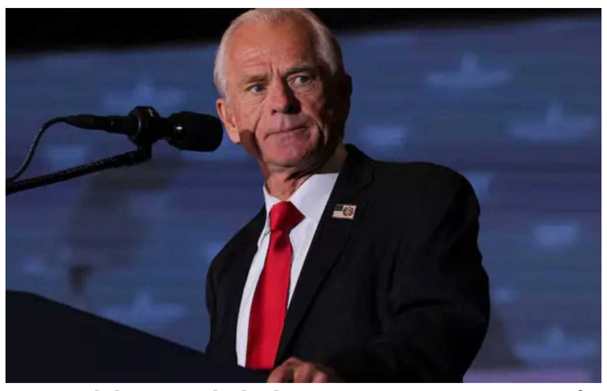

वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। नवारो ने यूक्रेन जंग को सीधे भारत से जोड़ते हुए इसे "मोदी वॉर" तक कह दिया। बुधवार को ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में नवारो ने भारत पर आरोप लगाया कि वह रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और ऊंची कीमत पर बेचता है। इस प्रक्रिया से रूस को युद्ध के लिए आवश्यक आर्थिक मदद मिलती है और वह यूक्रेन पर लगातार हमले करता जा रहा है। नवारो ने साफ शब्दों में कहा कि भारत का यह रवैया न केवल यूक्रेन जंग को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी खतरा है। उनके इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है, क्योंकि भारत अब तक खुद को "रणनीतिक स्वायत्तता" की नीति पर चलने वाला देश बताता रहा है।

भारत पर 'दोहरा खेल' खेलने का आरोप

नवारो ने अपने इंटरव्यू में भारत पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत पश्चिमी देशों से दोस्ती का दावा करता है, वहीं रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे आर्थिक रूप से मजबूत भी करता है।

उनके शब्दों में: "भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर ऊंची कीमत पर दुनिया को बेचता है। इससे रूस को युद्ध के लिए पैसा मिलता है और वही पैसा यूक्रेन के खिलाफ हथियारों में बदल जाता है।" नवारो ने इस तर्क से यह साबित करने की कोशिश की कि भारत के कारोबारी फैसले अप्रत्यक्ष रूप से रूस को ताकत दे रहे हैं।

"तानाशाहों के साथ खड़े हो रहे हो"

नवारो ने अपने बयान में भारत को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि रूस और चीन के साथ नजदीकियां दुनिया के लिए खतरनाक हैं। उन्होंने कहा - "भारत, तुम तानाशाहों के साथ खड़े हो रहे हो। चीन ने अक्साई चिन और तुम्हारे कई इलाके पर कब्जा कर लिया। रूस? जाने भी दो। ये तुम्हारे असली दोस्त नहीं हैं।" इस टिप्पणी से नवारो ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि भारत को अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए, न कि रूस और चीन जैसी ताकतों पर भरोसा करना चाहिए।

सौदे बंद करो, तो टैरिफ हटेगा

नवारो ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका के भारी-भरकम टैरिफ का बोझ भारत को तब तक झेलना होगा, जब तक वह रूस से तेल की खरीदारी बंद नहीं करता। उन्होंने कहा - "अगर भारत आज रूस से तेल के सौदे बंद कर दे, तो कल ही अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ हटा सकता है।" इस बयान से साफ है कि ट्रम्प कैंप भारत पर आर्थिक दबाव डालने की रणनीति बना रहा है।

भारत की ऊर्जा ज़रूरतें और पश्चिम की राजनीति

भारत का कहना है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल खरीद रहा है। भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है, जहां सस्ती ऊर्जा की भारी ज़रूरत है। ऐसे में रूस से मिलने वाला रियायती तेल भारत के लिए फायदेमंद साबित होता है। लेकिन पश्चिमी देशों का तर्क है कि यह खरीद-फरोख्त रूस को युद्ध के लिए धन मुहैया कराती है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप बार-बार भारत पर दबाव बनाते हैं कि वह रूस से दूरी बनाए।

ट्रम्प कैंप की राजनीतिक रणनीति

यह बयान केवल विदेश नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिकी घरेलू राजनीति से भी जुड़ा है। डोनाल्ड ट्रम्प और उनके सहयोगी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए आक्रामक रणनीति बना रहे हैं। ट्रम्प चाहते हैं कि वे मौजूदा प्रशासन से अलग और कठोर नजर आएं। भारत जैसे बड़े बाजार और उभरती ताकत पर दबाव डालना ट्रम्प की नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। अमेरिका अक्सर व्यापारिक समझौतों और टैरिफ का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है।

भारत के लिए संदेश

नवारो का बयान भारत के लिए स्पष्ट संदेश है कि अगर वह पश्चिमी दुनिया का भरोसा कायम रखना चाहता है तो उसे रूस-चीन से सावधानी बरतनी होगी।

मोदी-जिनपिंग 31 अगस्त को चीन में आमने-सामने

-सीमा विवाद पर वार्ता की उम्मीद

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 31 अगस्त को तियानजिन (चीन) में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) समिट के दौरान मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात कई लिहाज़ से अहम मानी जा रही है, क्योंकि 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद दोनों नेताओं की यह सिर्फ दूसरी औपचारिक भेंट होगी।

गलवान के बाद रिश्तों में कड़वाहट

जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प में भारत और चीन के कई जवान शहीद हुए थे। इस घटना ने दोनों देशों के रिश्तों को गहरा आघात पहुंचाया। उसके बाद से ही सीमा पर तनाव कायम है और कई दौर की सैन्य व कूटनीतिक वार्ताओं के बावजूद पूर्ण समाधान नहीं निकल पाया है।

पिछली मुलाकात और बनी सहमति

मोदी और जिनपिंग की आखिरी मुलाकात अक्टूबर 2024 में रूस के कज़ान शहर में हुई ब्रिक्स समिट के दौरान हुई थी। उस समय दोनों नेताओं ने बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने पर सहमति जताई थी। हालांकि, उसके बाद भी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर टकराव की स्थितियां समय-समय पर बनी रहीं।

तियानजिन मुलाकात की अहमियत

इस बार तियानजिन में होने वाली SCO समिट में 20 से अधिक देशों के नेता हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी न सिर्फ शी जिनपिंग बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और सेंट्रल एशिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। भारत के लिए यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के साथ सीमा विवाद पर फिर से सार्थक वार्ता की उम्मीद है। रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हो सकती है। मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार, सुरक्षा और संपर्क को लेकर नए समझौते संभव हैं।

सीमा विवाद पर केंद्रित वार्ता

मोदी-जिनपिंग मुलाकात में सीमा विवाद ही मुख्य एजेंडा रहने की संभावना है। भारत लगातार यह कहता आया है कि जब तक सीमाओं पर शांति और स्थिरता नहीं होगी, तब तक दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। चीन की ओर से भी हाल के महीनों में तनाव कम करने के संकेत दिए गए हैं।

भारत के लिए रणनीतिक संतुलन

भारत की यह मुलाकात सिर्फ चीन के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक बड़े रणनीतिक संतुलन का हिस्सा भी है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए, चीन भी संबंधों में सुधार चाहता है। दूसरी ओर, रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते भारत और रूस के रिश्तों में भी नई अहमियत जुड़ गई है। 31 अगस्त को होने वाली मोदी-जिनपिंग मुलाकात केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि सीमा विवाद के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। दुनिया की नज़र इस मुलाकात पर होगी कि क्या दोनों एशियाई महाशक्तियां गलवान के घावों को पीछे छोड़कर रिश्तों में नई शुरुआत कर पाएंगी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 31 अगस्त को तियानजिन में होने वाली मुलाकात केवल औपचारिक बातचीत नहीं, बल्कि एशिया की बदलती राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। भारत और चीन, दोनों एशियाई महाशक्तियाँ, बीते चार साल से गलवान झड़प की कड़वाहट को ढो रही हैं। इस पृष्ठभूमि में यह मुलाकात रिश्तों में नरमी लाने की संभावना जगा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार की बैठक में सीमा विवाद ही मुख्य मुद्दा रहेगा। भारत स्पष्ट कर चुका है कि जब तक सीमा पर शांति और स्थिरता नहीं होगी, तब तक द्विपक्षीय रिश्ते में सामान्यता संभव नहीं है। चीन भी अपनी ओर से वार्ता के लिए तैयार दिख रहा है, क्योंकि एशिया में बढ़ते अमेरिकी प्रभाव से वह चिंतित है। मोदी का यह दौरा केवल चीन तक सीमित नहीं रहेगा। वे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और मध्य एशिया के कई नेताओं से भी मिलेंगे। इससे भारत की कूटनीति को एक संतुलित दिशा मिलेगी। ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और व्यापार बढ़ाने जैसे मुद्दे भी चर्चाओं में रहेंगे। कुल मिलाकर, यह मुलाकात भारत-चीन रिश्तों में नई शुरुआत का आधार बन सकती है, बशर्ते दोनों देश सीमा पर विश्वास बहाली के ठोस कदम उठाएँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 31 अगस्त को तियानजिन (चीन) में होने वाली मुलाकात शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) समिट का सबसे अहम क्षण मानी जा रही है।

विरार हादसा: चार मंजिला बिल्डिंग गिरने से 17 की मौत, बर्थडे पार्टी बनी मातमगाह

मुंबई। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में सोमवार रात हुआ दिल दहला देने वाला हादसा पूरे इलाके को झकझोर गया। विजय नगर इलाके में स्थित रमाबाई अपार्टमेंट की चार मंजिला बिल्डिंग अचानक ध्वस्त हो गई। इस हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर एक साल की बच्ची का जन्मदिन मनाया जा रहा था। खुशियों का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया।

हादसा कैसे हुआ

जानकारी के अनुसार, 26 अगस्त की रात ठीक 12 बजकर 5 मिनट पर यह हादसा हुआ। रमाबाई अपार्टमेंट में करीब 50 फ्लैट बने हुए थे। देर रात अचानक इसकी 12 फ्लैटें बगल में बने एक खाली पड़े पुराने मकान पर गिर पड़ीं। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की कॉलोनियों में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय निवासियों और चश्मदीदों का कहना है कि हादसा बेहद भयावह था। लोग मलबे में दबे लोगों की चीखें सुन रहे थे, लेकिन अंधेरा और भारी मलबा होने की वजह से तुरंत मदद करना आसान नहीं था।

बर्थडे पार्टी बनी मातमगाह

हादसे के वक्त चौथी मंजिल पर एक साल की मासूम बच्ची का जन्मदिन मनाया जा रहा था। रिश्तेदार और दोस्त जमा थे। अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगी और देखते ही देखते पार्टी की रौनक खामोशी में बदल गई। बच्ची, उसकी मां और कई मेहमान इस मलबे के नीचे दब गए। सुबह तक चले रेस्क्यू अभियान में उनके शव बाहर निकाले गए। इस घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया।

रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं। मंगलवार सुबह तक राहत और बचाव कार्य लगातार जारी रहा। भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम किया गया। पहले दिन 12 लोगों के शव निकाले गए थे और बुधवार सुबह तक 5 और शव मिले। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

स्थानीय प्रशासन ने घटना पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। साथ ही घायलों के मुफ्त इलाज के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि बिल्डिंग की मजबूती को लेकर पहले भी शिकायतें मिली थीं। हादसे के बाद अब पूरे इलाके में ऐसी इमारतों का सर्वे किया जाएगा, जो जर्जर हालत में हैं।

जिम्मेदारी का सवाल

यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग अचानक क्यों गिर गई? प्रारंभिक जांच में संभावना जताई जा रही है कि इमारत पुरानी थी और रख-रखाव नहीं हुआ।

मुद्रक, प्रकाशक व स्वत्वाधिकारी मुन्ना खान के लिए श्री राम ऑफसेट, 6, शॉपिंग सेंटर, जोरावर सिंह गेट के बाहर, आमेर रोड, जयपुर से मुद्रित तथा रॉयल पत्रिका कार्यालय 4312 मोहल्ला नायकों का, जगन्नाथ शाह का रास्ता, नाहरबाड़ा, रामगंज, जयपुर से प्रकाशित। संपादक मुन्ना खान मो. 08058969180 कार्यालय फोन- 0141-2609886,